

राष्ट्रपति का अभिभाषण: 2025 की घोषणाओं की स्थिति

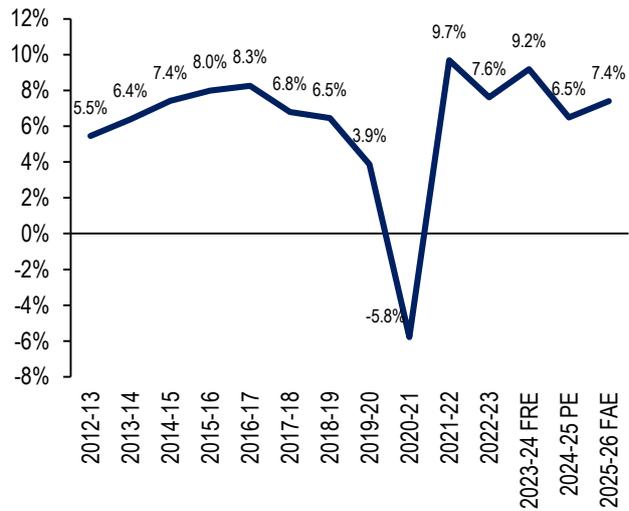
संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की पहली बैठक में संसद को संबोधित करना होता है। इस अभिभाषण में राष्ट्रपति द्वारा सरकार की प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताओं को रेखांकित किया जाता है। इस नोट में जनवरी 2025 में राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रमुख घोषणाओं (ग्रे रंग में) और घोषित पहलों की नवीनतम स्थिति का उल्लेख किया गया है।¹ आंकड़ों से संबंधित स्रोत एंडनोट्स में मौजूद हैं।

अर्थव्यवस्था एवं वित्त

आर्थिक विकास: सरकार भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में अग्रसर है।

- भारत 2025 में वर्तमान कीमतों (USD में) पर जीडीपी के मामले में विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जो 2013-14 में 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी।² 2025 में भारत की जीडीपी लगभग 4.1 ट्रिलियन USD थी।²
- आरबीआई ने 2025-26 के लिए वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर 7.4% (स्थिर कीमतों पर) रहने का अनुमान लगाया है, जबकि 2024-25 में यह 6.5% थी।³

रेखाचित्र 1: स्थिर कीमतों पर जीडीपी वृद्धि (प्रतिशत में)



तालिका 1: 2025 में जीडीपी और प्रति व्यक्ति जीडीपी

देश	जीडीपी (ट्रिलियन USD में)		प्रति व्यक्ति जीडीपी (USD में)	
	वैल्यू	रैंक	वैल्यू	रैंक
यूएसए	30.6	1	89,599	8
चीन	19.4	2	13,806	77
जर्मनी	5	3	59,925	18
जापान	4.3	4	34,713	39
भारत	4.1	5	2,818	144

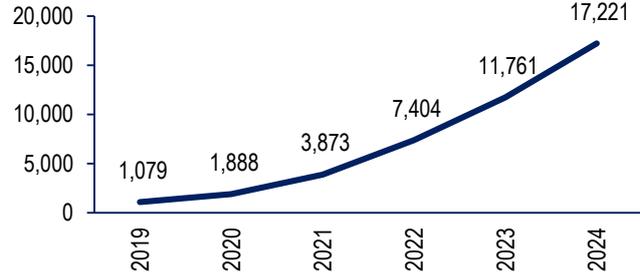
नोट: PE अनंतिम अनुमान है। FRE प्रथम संशोधित अनुमान है। FAE प्रथम अग्रिम अनुमान है। स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; पीआरएस।

नोट: यह रैंकिंग 188 देशों में से है। स्रोत: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष; पीआरएस।

बैंकिंग क्षेत्र के सुधार: अब गांवों में भी बैंकिंग सेवाएं और यूपीआई जैसी विश्व स्तरीय तकनीक उपलब्ध हैं। विश्व के 50% से अधिक रियल टाइम डिजिटल लेनदेन अब भारत में होते हैं।

- 2019 और 2024 के बीच प्रति वर्ष यूपीआई लेनदेन की संख्या 74% की वार्षिक दर (सीएजीआर) से बढ़ी है। यह 2019 में लगभग 1,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024 में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है।⁴
- सरकार के अनुसार, यूपीआई प्रणाली 49 करोड़ व्यक्तियों और 6.5 करोड़ व्यापारियों को सेवा प्रदान करती है और 675 बैंकों से जुड़ी हुई है।⁵ यह प्लेटफॉर्म प्रतिदिन 64 करोड़ लेनदेन का संचालन करता है, जबकि वीज़ा द्वारा 63 करोड़ लेनदेन किए जाते हैं।⁵

रेखाचित्र 2: एक वर्ष में यूपीआई लेनदेन की मात्रा (करोड़ में)



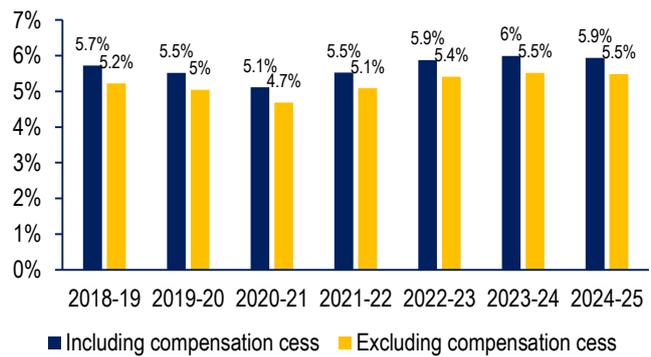
स्रोत: भुगतान प्रणाली की रिपोर्ट (2025), भारतीय रिजर्व बैंक; पीआरएस।

- प्रधानमंत्री जन धन योजना वर्ष 2014 में उन परिवारों को वित्तीय सेवाएं, जैसे कि ऋण और बीमा, उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी जिनके बैंक खाते नहीं थे।⁶ इस योजना के अंतर्गत खातों की संख्या 2015 में लगभग 14.7 करोड़ से बढ़कर 2025 में 57 करोड़ हो गई है।⁶ इनमें से लगभग 67% खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं, जबकि 33% खाते शहरी और महानगरों में स्थित हैं।⁶
- मंत्रालय के अनुसार, दिसंबर 2025 तक 57 करोड़ खातों में से लगभग 15 करोड़ (26%) खाते निष्क्रिय थे (जिनमें दो वर्षों से कोई ग्राहक लेनदेन नहीं हुआ था)।⁷ इसके अलावा, लगभग 9% खाते (5.2 करोड़) शून्य शेष वाले खाते थे।⁷

जीएसटी का संग्रह: 'एक राष्ट्र, एक कर' की भावना के साथ जीएसटी प्रणाली शुरू की गई थी जिससे देश भर के सभी राज्यों को लाभ मिल रहा है।

- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जून 2017 में लागू किया गया था।⁸ जीएसटी व्यवस्था के तहत पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। बिक्री कर और उत्पाद शुल्क जैसे कर इसके तहत आते हैं। सितंबर 2025 में जीएसटी की दरों को सुव्यवस्थित किया गया।⁹
- 2024-25 में जीएसटी संग्रह लगभग 20 लाख करोड़ रुपए (जीडीपी का 5.9%) था, जिसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर शामिल है। जीडीपी के अनुपात में जीएसटी के तहत राजस्व, जीएसटी-पूर्व व्यवस्था की तुलना में कम रहा है। 2015-16 में जीएसटी के

रेखाचित्र 3: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जीएसटी राजस्व



नोट: जीएसटी राजस्व से तात्पर्य केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जीएसटी आय से है। रेखाचित्र में 2017-18 को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि जीएसटी इस वर्ष के कुछ ही महीनों में लागू हुआ था। स्रोत: जीएसटी नेटवर्क; केंद्रीय बजट दस्तावेज़; एमओएसपीआई; पीआरएस।

अंतर्गत शामिल करों से राजस्व जीडीपी का लगभग 6.5% था। 15वें वित्त आयोग ने मध्यम अवधि में जीडीपी के मुकाबले जीएसटी अनुपात के 7% तक पहुंचने की संभावना जताई है (यह अनुपात क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त राजस्व को हटाकर है)।¹⁰

कृषि

खाद्यान्न का उत्पादन: 2023-24 में भारत ने खाद्यान्न का रिकॉर्ड 332 मिलियन टन उत्पादन हासिल किया।

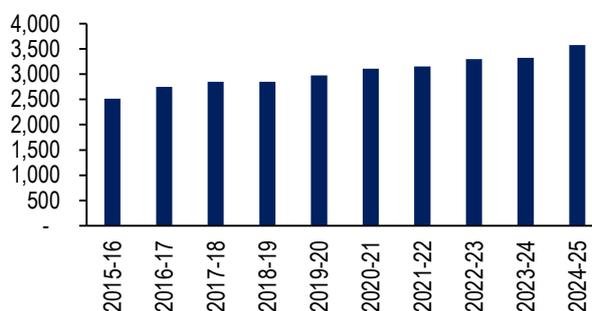
- 2024-25 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 357 मिलियन टन तक पहुंच गया।¹¹ इसमें से गेहूं का उत्पादन 118 मिलियन टन और चावल का उत्पादन 149 मिलियन टन होने का अनुमान है।¹¹
- खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार, अनाज, चावल और दालों की खेती के लिए आवंटित क्षेत्रफल के मामले में भारत शीर्ष देशों में शुमार है।^{12,13} हालांकि, भारत में प्रमुख फसलों की पैदावार कम है।

तालिका 2: वर्ष 2022-23 में प्रमुख फसलों की औसत उपज (किलोग्राम/हेक्टेयर में)

फसल	भारत	विश्व में सर्वाधिक	विश्व का औसत
धान	4,229	7,080	4,705
गेहूं	3,537	8,590	-
मक्का	3,387	10,880	5,718
गन्ना	78,600	94,400	70,600

स्रोत: खरीफ फसलों के लिए मूल्य नीति, 2025-26, कृषि लागत और मूल्य आयोग; पीआरएस।

रेखाचित्र 4: भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन (लाख टन में)



स्रोत: खाद्यान्न उत्पादन का अंतिम अनुमान 2024-25, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, 2025; पीआरएस।

तालिका 3: भारत में चयनित खाद्यान्नों का उत्पादन, 2020-21 से 2024-25 तक (लाख टन में)

फसल	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
चावल	1,244	1,295	1,358	1,378	1,502
गेहूं	1,096	1,077	1,106	1,133	1,179
मक्का	316	337	381	377	434
अनाज	513	511	573	569	639

स्रोत: खाद्यान्न उत्पादन का अंतिम अनुमान 2024-25, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, 2025; पीआरएस।

कृषि अवसंरचना: कृषि अवसंरचना की मजबूती के लिए कृषि अवसंरचना निधि योजना का दायरा बढ़ाया गया है।

- कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) की शुरुआत 2020 में कृषि अवसंरचना को मजबूत करने के लिए की गई थी जिसका उद्देश्य फार्म गेट स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना था।¹⁴ इस कोष के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था जिससे ऋण देने वाली संस्थाओं के जरिए 9% तक की ब्याज दर पर ऋण वितरित किए जाते हैं।¹⁵
- अगस्त 2024 में एआईएफ योजना का विस्तार किया गया: (i) वित्त पोषण सुविधा की अवधि को 2023-24 से बढ़ाकर 2025-26 किया गया, (ii) योजना की कुल परिचालन अवधि को 2029-30 से बढ़ाकर 2032-33 तक किया गया, (iii) पात्र लाभार्थियों का दायरा बढ़ाया गया जिसमें अब कृषि उपज मंडी समितियां और राज्य एजेंसियां भी शामिल हैं, और (iv) पात्र परिसंपत्तियों के दायरे को विस्तृत किया गया जिसमें केवल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे की बजाय अब एकीकृत प्रसंस्करण परियोजनाओं और सामुदायिक स्तर की खेती से जुड़े बुनियादी ढांचे को भी शामिल किया गया है।¹⁶
- एआईएफ के तहत नवंबर 2025 तक 78,579 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जा चुके हैं।¹⁷ इन ऋणों के माध्यम से प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों, गोदामों, छंटाई और वर्गीकरण इकाइयों और कोल्ड स्टोरेज परियोजनाओं सहित लगभग 1.45 लाख परियोजनाओं को धनराशि प्रदान की गई है।¹⁷
- 2020-21 में कृषि उपज की हानि लगभग 69 मिलियन मीट्रिक टन (कुल का 5.5%) अनुमानित की गई थी जिससे लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का मौद्रिक नुकसान हुआ।¹⁸

प्राकृतिक कृषि: प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

- राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन को नवंबर 2024 में मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 2,481 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था।¹⁹ इसका उद्देश्य कृषि की सतत प्रणालियों को बढ़ावा देना, खेतों पर ही बने प्राकृतिक खेती के जैव इनपुट्स के उपयोग को बढ़ाना और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना है। इसके अलावा, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना के तहत दो वर्षों तक प्रति एकड़ प्रति वर्ष 4,000 रुपए का प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है।²⁰ इसका उद्देश्य 2026 तक 7.5 लाख हेक्टेयर (कृषि भूमि का लगभग 0.5%) भूमि पर प्राकृतिक कृषि की शुरुआत करना है। मिशन को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लागू किया जाएगा, जैसे: (i) गंगा नदी के किनारे पांच किलोमीटर के गलियारे वाले क्षेत्र, (ii) प्रमुख नदियों के तटवर्ती जिले, (iii) राज्यों के वे जिले जहां उर्वरक की बिक्री बहुत अधिक या बहुत कम है, और (iv) जनजातीय क्षेत्रों वाले जिले।
- अक्टूबर 2025 तक मिशन के अंतर्गत 54.5 लाख हेक्टेयर भूमि को शामिल किया जा चुका है।²¹ अगस्त 2025 तक राज्यों को 304 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं और लगभग 11 लाख किसानों का पंजीकरण हो चुका है।²² लास्ट-माइल इनपुट डिलिवरी और और किसानों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए 70,000 कृषि सखियों को प्रशिक्षित किया गया है।¹⁹

न्यूनतम समर्थन मूल्य: सरकार ने खरीफ और रबी, दोनों फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में लगातार वृद्धि की है। पिछले एक दशक में चावल, गेहूं, दालों, तिलहन और मोटे अनाज की खरीद पर खर्च तीन गुना हो गया है।

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) वह सुनिश्चित मूल्य है जिस पर केंद्र और राज्य सरकारें किसानों से कृषि उपज खरीदती हैं।²³ 2006 में राष्ट्रीय किसान आयोग (चेयर: डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन) ने सुझाव दिया था कि एमएसपी उत्पादन लागत से कम से कम 50% अधिक हो।²⁴ 2018-19 में केंद्र सरकार ने घोषणा की कि वह एमएसपी को उत्पादन लागत के 1.5 गुना पर निर्धारित करेगी, जो कि ए2+एफएल लागत पर आधारित है।²⁵ ए2 फसल उत्पादन में लगने वाली लागत को दर्शाता है, और एफएल पारिवारिक श्रम की लागत को दर्शाता है। ए2+एफएल में कुछ अन्य लागतें जैसे किराया और पूंजीगत परिसंपत्तियों पर ब्याज शामिल नहीं हैं। **तालिका 4** में सी2 इन लागतों को शामिल करने के बाद की उत्पादन लागत है।
- 2024-25 में कुल चावल खरीद का लगभग आधा हिस्सा (50.2%) पंजाब, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से प्राप्त हुआ।²⁶ उसी वर्ष कुल खरीद में पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश का हिस्सा लगभग 93% रहा।²⁶

तालिका 4: 2025-26 में कुछ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (रुपए प्रति क्विंटल में)

फसल	उत्पादन की लागत			ए2+एफएल के अनुपात के रूप में एमएसपी	सी2 के अनुपात के रूप में एमएसपी
	ए2 +एफएल	सी2	एमएसपी		
धान	1,579	2,090	2,369	1.5	1.1
गेहूं	1,239	1,804	2,585	2.1	1.4
ज्वार	2,466	3,206	3,699	1.6	1.3
बाजरा	1,703	2,909	2,775	2.9	1.3
मक्का	1,508	1,952	1,952	1.6	1.2
जौ	1,361	1,862	2,150	1.6	1.2
चना	3,699	4,875	5,875	1.6	1.2

स्रोत: सीएसीपी द्वारा अनुशंसित और सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 2025; पीआरएस।

- तिलहन, दालों और खोपरा के उत्पादन के लिए किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) को 2018 में शुरू किया गया था।²⁷ सितंबर 2024 में पीएम-आशा में दो योजनाओं (मूल्य समर्थन योजना और बाजार हस्तक्षेप योजना) को शामिल किया गया जिनके तहत सरकार कुछ फसलों की खरीद तब करती थी जब उनकी कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम हो जाती थी या पिछले वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती थी।²⁷

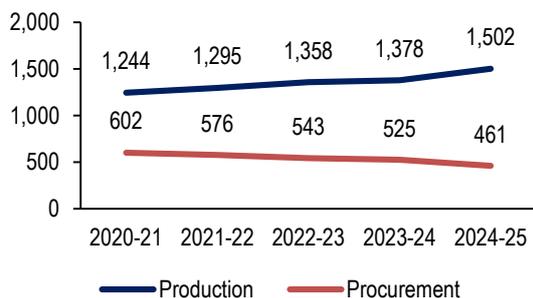
तालिका 5: वर्ष 2024-25 में चावल और गेहूं की खरीद में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाले राज्य

राज्य	गेहूं		चावल	
	खरीद की हिस्सेदारी (%)	राज्य	खरीद की हिस्सेदारी (%)	राज्य
पंजाब	47.4	पंजाब	25.1	
हरियाणा	27.3	छत्तीसगढ़	15.1	
मध्य प्रदेश	18.2	ओड़िशा	10	
उत्तर प्रदेश	3.5	उत्तर प्रदेश	8.4	
राजस्थान	3.7	अन्य	41.4	

स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 2963, लोकसभा, 18 मार्च 2025; पीआरएस।

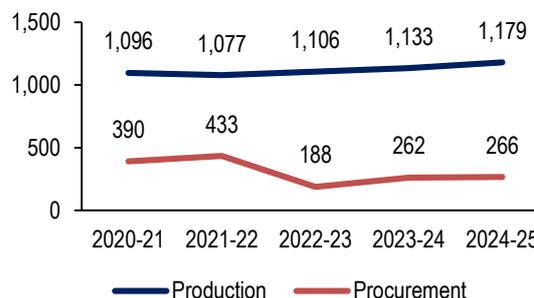
- पीएम-आशा योजना (मूल्य घाटा भुगतान योजना) के एक घटक के तहत, जब बाजार मूल्य एमएसपी से कम होता है, तो सरकार तिलहन के लिए एमएसपी और बाजार मूल्य के बीच का अंतर चुकाती है।²⁷ 2018-19 से अब तक पीएम-आशा योजना के तहत 195 लाख मीट्रिक टन दालों, तिलहन और खोपरा की खरीद के माध्यम से 99 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया गया है।²⁷
- केंद्र सरकार ने दालों की खरीद के लिए एक नए मिशन की घोषणा की है। इसमें तुअर, उड़द और मसूर पर विशेष जोर दिया जाएगा।²⁸ योजना के लिए वर्ष 2025-26 के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।²⁸

रेखाचित्र 5: 2020-21 से 2024-25 तक चावल का उत्पादन एवं खरीद (लाख टन में)



स्रोत: 2024-25 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का अंतिम अनुमान; कृषि सांख्यिकी एक नज़र में 2024; पीआरएस।

रेखाचित्र 6: वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक गेहूं का उत्पादन एवं खरीद (लाख टन में)

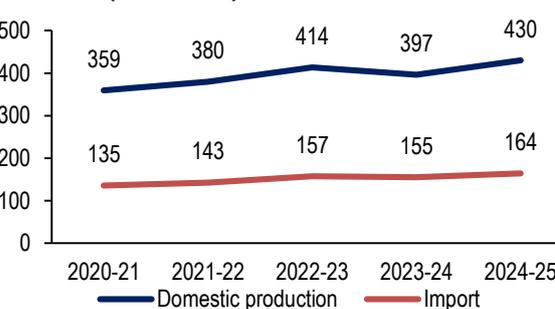


स्रोत: 2024-25 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का अंतिम अनुमान; कृषि सांख्यिकी एक नज़र में 2024; पीआरएस।

तिलहन: तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तिलहन पर एक राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी गई है।

- तिलहन का घरेलू उत्पादन 2023-24 में 397 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 430 लाख टन हो गया, जो 8.3% की वृद्धि है।²⁹ 2024-25 में 164 लाख टन खाद्य तेल आयात किया गया, जो 2023-24 में 155 लाख टन से बढ़कर 6.5% की वृद्धि है।²⁹
- घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता पैदा करने के लिए अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- पाम ऑयल का शुभारंभ किया गया था।²⁹ इसे 2024-25 और 2030-31 के बीच 10,103 करोड़ रुपए के

रेखाचित्र 7: तिलहनों का घरेलू उत्पादन और खाद्य तेलों का आयात (लाख टन में)



स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 2553, लोकसभा, डीएण्डएफडब्ल्यू, दिसंबर 2025; पीआरएस।

परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है।²⁹
 इसका उद्देश्य 2030-31 तक प्राथमिक तिलहन
 उत्पादन को 697 लाख टन तक बढ़ाना है।²⁹

महिला एसएचजी: मेरी सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदियों का लक्ष्य रखा है। आज 1.15 करोड़ से अधिक लखपति दीदियां सम्मानजनक जीवन जी रही हैं जिनमें से लगभग 50 लाख दीदियां पिछले छह महीनों में ही लखपति दीदी बनी हैं। ड्रोन दीदी योजना महिलाओं के आर्थिक और तकनीकी सशक्तिकरण का एक माध्यम बन गई है।

- लखपति दीदी, दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत एक पहल है। डीएवाई-एनआरएलएम का उद्देश्य गरीब परिवारों, विशेषकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करके और उन्हें आजीविका के अवसर और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करके ग्रामीण गरीबी को कम करना है।³⁰ मिशन लखपति दीदी, एसएचजी की वह सदस्य होती है जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय कम से कम एक लाख रुपए हो और औसत मासिक आय कम से कम 10,000 रुपए हो।³¹ आय कम से कम चार कृषि ऋतुओं और/या व्यावसायिक चक्रों तक निरंतर बनी रहनी चाहिए। केंद्रीय बजट 2024-25 में इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य को दो करोड़ व्यक्तियों से बढ़ाकर तीन करोड़ व्यक्ति कर दिया गया था।³¹ अगस्त 2025 तक 1.5 करोड़ एसएचजी सदस्य लखपति दीदी बन चुके थे।³²
- नवंबर 2024 में शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना का उद्देश्य महिला एसएचजीज को ड्रोन उपलब्ध कराना है, जिन्हें कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को किराए पर दिया जा सकता है।³³ यह योजना ड्रोन की लागत का 80% तक, अधिकतम आठ लाख रुपए तक की सबसिडी प्रदान करती है।³³ 2023-24 और 2025-26 के बीच की अवधि के लिए योजना का अनुमानित परिव्यय 1,261 करोड़ रुपए है।³⁴ 2024-25 में योजना का लक्ष्य 3,090 स्वयं सहायता समूहों को 15,000 ड्रोन वितरित करना है।³³ उर्वरक कंपनियों, जो राज्यों के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक हैं, ने योजना के तहत 500 ड्रोन खरीदे और वितरित किए थे।³⁵

किसानों को आय समर्थन: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हाल के महीनों में करोड़ों किसानों को 41,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं।

- भूमिधारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी।³⁶ इस योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए तीन बराबर किस्तों में दिए जाते हैं। यह राशि किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीएल) के माध्यम से भेजी जाती है। योजना की शुरुआत से लेकर दिसंबर 2025 तक किसानों को 21 किस्तों में 4.1 लाख करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं।³⁷

रेखाचित्र 8: प्रधानमंत्री-किसान योजना के तहत लाभार्थियों की किस्तवार संख्या (करोड़ में)

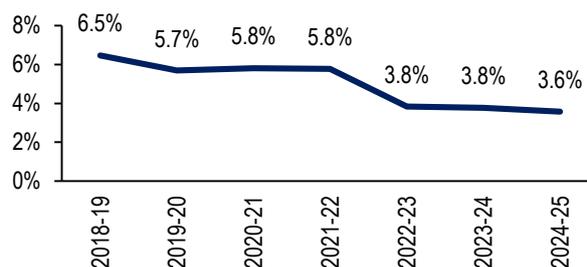


स्रोत: तारांकित प्रश्न संख्या 23, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, लोकसभा, 22 जुलाई 2025; पीआरएस।

दूध और दालों का उत्पादन: आज भारत विश्व में दूध, दालों और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है।

- 2025 में भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक था और वैश्विक दूध उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 25% थी।³⁸ 2016-17 और 2022-23 के बीच, भारत के दूध उत्पादन में 5.7% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई।³⁹ हालांकि, दूध उत्पादन में वार्षिक वृद्धि दर 2018-19 में 6.5% से घटकर 2024-25 में 3.6% हो गई है। घरेलू दूध उत्पादन 2024-25 में 248 मिलियन टन था, जबकि 2021-22 में यह 222 मिलियन टन था।³⁹
- वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में मवेशियों की औसत वार्षिक उत्पादकता 1,777 किलोग्राम प्रति पशु प्रति वर्ष थी, जबकि विश्व औसत 2,699 किलोग्राम प्रति पशु प्रति वर्ष था।⁴⁰

रेखाचित्र 9: भारत में दूध उत्पादन की वृद्धि दर

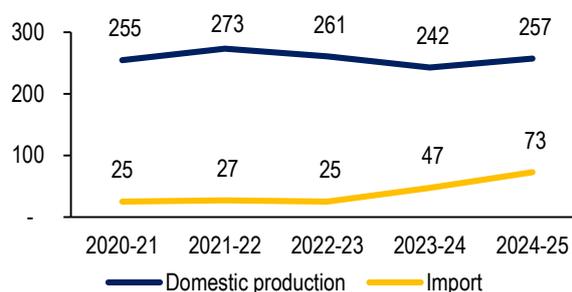


स्रोत: बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2025, पशुपालन और डेयरी विभाग; पीआरएस।

वर्ष 2013-14 और 2019-20 के बीच मवेशियों की औसत उत्पादकता में 28% की वृद्धि हुई है।⁴⁰ वर्ष 2024-25 में भारत में प्रति व्यक्ति दूध की आपूर्ति 485 ग्राम प्रतिदिन थी, जबकि विश्व औसत 322 ग्राम था। पंजाब में दूध की उपलब्धता सबसे अधिक (1,318 ग्राम) थी, जबकि महाराष्ट्र में सबसे कम (358 ग्राम) थी।⁴⁰

- 2022 में भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक था और वैश्विक उत्पादन में इसका 28% हिस्सा था।⁴¹ हालांकि भारत की उपज अपेक्षाकृत कम है। भारत की औसत दाल उपज 0.74 टन प्रति हेक्टेयर थी, जो वैश्विक औसत 0.97 टन प्रति हेक्टेयर से कम है।⁴¹ भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात पर भी निर्भर है (रेखाचित्र 10)।

रेखाचित्र 10: भारत में दलहन का घरेलू उत्पादन और आयात (लाख टन में)



स्रोत: अतारंकित प्रश्न संख्या 2553, लोकसभा, दिसंबर 2025; 2024-25 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का अंतिम अनुमान; पीआरएस।

किसानों की आय: मेरी सरकार किसानों को फसलों की उचित कीमत सुनिश्चित करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए पूरी लगन से काम कर रही है।

- किसानों की आय में सुधार लाने के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं लागू की हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
 - प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आय सहायता प्रदान की जाती है;
 - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके तहत किसानों को प्राकृतिक आपदा, कीटों और रोगों से फसल के नुकसान से बीमा प्रदान किया जाता है;
 - प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, जिसके तहत किसानों को

सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाती है; और (iv) न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण, जो किसानों को सुनिश्चित मूल्य और बाजार में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करता है।⁴²

- फसल उत्पादन से औसत मासिक आय 2018-19 में 3,932 रुपए थी जो 2012-23 (3,081 रुपए) की तुलना में 4.1% की वार्षिक वृद्धि है।^{43,44} कृषि परिवार की औसत कुल मासिक आय 2018-19 में 10,218 रुपए प्रति माह अनुमानित थी जो 2012-13 (6,426 रुपए) की तुलना में 8% की वृद्धि है।^{43,44} इस आय में फसल उत्पादन, पशुपालन, मजदूरी और गैर कृषि व्यवसाय से होने वाली आय शामिल है।

तालिका 6: वर्ष 2012-13 और 2018-19 में कृषि परिवारों की औसत मासिक आय (रुपए में)

विशेष	2012-13		2018-19		12-13 से 18-19 तक वार्षिक परिवर्तन
	राशि	% हिस्सा	राशि	% हिस्सा	
कुल मासिक आय	6,426	-	10,218	-	8.0%
इनमें से					
फसल उत्पादन से आय	3,081	48%	3,932*	38%	4.1%
पशुपालन से आय	763	12%	1,582	15%	12.9%
मजदूरी से आय	2,071	32%	4,063	40%	11.9%
गैर-कृषि व्यवसाय से आय	512	8%	641	6%	3.8%

नोट: *इसमें भूमि पट्टे (लीज) पर देने से प्राप्त 134 रुपए की औसत मासिक आय शामिल है जिसे अलग से रिपोर्ट किया गया है। स्रोत: एंडनोट 43 और 44 देखें; पीआरएस।

इंफ्रास्ट्रक्चर

रेलवे: वर्तमान में, देशभर में 71 वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनें चल रही हैं, जिनमें पिछले छह महीनों में 17 नई वंदे भारत ट्रेनें और एक नमो भारत ट्रेन जोड़ी गई हैं।

- दिसंबर 2025 तक 164 वंदे भारत ट्रेन, 30 अमृत भारत ट्रेन और 2 नमो भारत ट्रेन चल रही हैं।⁴⁵ वर्ष 2025 में 15 वंदे भारत ट्रेन और 13 अमृत भारत ट्रेन शुरू की गईं।⁴⁵
- रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जनवरी 2026 में असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच चलेगी।⁴⁶

तालिका 7: रेलवे ट्रेक की गति क्षमता (किलोमीटर में)

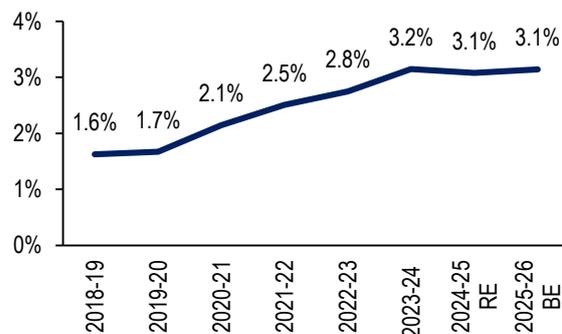
विशेष खंड पर गति (kmph)	2014		2025*	
130 और उससे अधिक	5,036	6%	23,010	22%
110 -130	26,409	33%	60,726	57%
<130	47,897	60%	21,936	21%
कुल	79,342	100	1,05,672	100

नोट: * नवंबर 2025 तक के आंकड़े। स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 1639, लोकसभा, रेल मंत्रालय, 10 दिसंबर 2025; पीआरएस।

इंफ्रास्ट्रक्चर: दस साल पहले पूंजीगत व्यय का बजट लगभग 2 लाख करोड़ रुपए था, जो पिछले बजट में बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।

- केंद्रीय बजट 2025-26 में पूंजीगत व्यय के लिए 11.2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे।⁴⁷ पूंजीगत व्यय 2018-19 में जीडीपी के 1.6% से बढ़कर 2025-26 में जीडीपी के 3.1% हो गया है (रेखाचित्र 11)।

रेखाचित्र 11: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय



नोट: RE का अर्थ है संशोधित अनुमान। BE का अर्थ है बजट अनुमान। स्रोत: संबंधित वर्षों के बजट दस्तावेज; पीआरएस।

तालिका 8: वर्ष 2025-26 के बजट में सबसे अधिक पूंजीगत व्यय आवंटित करने वाले मंत्रालय

मंत्रालय	कैपेक्स आवंटन	कुल कैपेक्स बजट का %
सड़क परिवहन और राजमार्ग	2,72,241	24%
रेलवे	2,52,000	22%
वित्त	2,21,534	20%
रक्षा	1,92,388	17%

स्रोत: अनुदान मांग पर नोट्स, 2025-2026; पीआरएस।

ई-बस: देश में 8,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 52,000 इलेक्ट्रिक बसों को तैनात करने का निर्णय सुगम और स्वच्छ शहरी परिवहन प्रदान करेगा।

- प्रधानमंत्री की इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति (E-DRIVE) योजना सितंबर 2025 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 14,028 ई-बसों की तैनाती के लिए 4,391 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।⁴⁸
- प्रधानमंत्री ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना अक्टूबर 2024 में शुरू की गई थी।⁴⁹ इस योजना के लिए 3,435 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है और इसका उद्देश्य 38,000 इलेक्ट्रिक बसों को तैनात करना है। यह योजना 2024-25 से 2028-29 तक लागू रहेगी।⁴⁹ दिसंबर 2025 तक 13 राज्यों ने भारतीय रिजर्व बैंक को डायरेक्ट डैबिट मैसेज जमा कर दिया है जो इस योजना के तहत पात्रता के लिए आवश्यक है।⁵⁰

मेट्रो रेल: भारत के मेट्रो नेटवर्क ने 1,000 किलोमीटर का आंकड़ा पार कर लिया है। मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है।

- दिसंबर 2025 तक 25 शहरों में लगभग 1,083 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइनें चालू हैं।⁵¹ इनमें से 40% से अधिक लाइनें दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में हैं।
- आर्थिक सर्वेक्षण (2025) में यह उल्लेख किया गया है कि भारत में सभी मेट्रो और रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में प्रतिदिन यात्रियों की औसत संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है।⁵²

तालिका 9: दिसंबर 2025 तक राज्यवार परिचालित मेट्रो की लंबाई

राज्य/यूटी	संचालित मेट्रो शहर	संचालित लंबाई (किमी)
दिल्ली और एनसीआर	दिल्ली+एनसीआर के शहर	451
महाराष्ट्र	मुंबई, नागपुर, पुणे	184
कर्नाटक	बेंगलुरु	96
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	73
अन्य राज्य	विभिन्न शहर	279

स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 3110, लोकसभा, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, 18 दिसंबर 2025; पीआरएस।

उड़यन: उड़ान योजना के माध्यम से लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने हवाई जहाज में उड़ान भरने का अपना सपना पूरा किया है।

- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना-उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) नवंबर 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य मार्गों की पहचान करके और ऑपरेटरों को सबसिडी और एकाधिकार प्रदान करके टियर-2 और टियर-3 शहरों में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है।⁵³
- नवंबर 2025 तक 93 ऐसे हवाई अड्डों को जोड़ने वाले 651 क्षेत्रीय मार्गों को चालू किया जा चुका है, जहां पहले हवाई सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं या कम उपलब्ध थीं।⁵³ इस योजना के तहत 3.3 करोड़ आरसीएस उड़ानों में लगभग 1.6 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की है।⁵³ नागरिक उड़यन मंत्रालय ने अनुसार, 272 आरसीएस मार्गों पर परिचालन अभी शुरू होना बाकी है। इसके पीछे हवाई अड्डों का विकासशील होना या योजना चरण में होना, चयनित एयरलाइन ऑपरेटर्स के पास विमानों की अनुलब्धता और वाणिज्यिक रूप से गैर व्यवहार्य होने जैसे कारण हैं।⁵⁴

क्षेत्रीय विकास: मेरी सरकार ने देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया है, जो सुशासन का एक अनूठा प्रयोग है। इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप इन जिलों में स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

- सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े 112 जिलों के उत्थान के लिए 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया गया था।⁵⁵ यह योजना कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में कुछ प्रमुख संकेतकों पर नज़र रखती है।
- 2025 में 71 में से 51 जिलों में प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर तक संक्रमण दर 90% से अधिक थी जबकि 71 में से 32 जिलों में उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय स्तर तक संक्रमण दर 90% से अधिक थी।⁵⁶ कृषि क्षेत्र में 50 में से 7 जिलों में रबी फसलों के लिए फसल बीमा दर 50% से अधिक थी।⁵⁶ खरीफ फसलों के लिए 54 में से 13 जिलों में फसल बीमा दर 50% से अधिक थी। 75 जिलों में से 58 जिलों में 90% से अधिक गर्भवती महिलाओं की 4 या अधिक प्रसवपूर्व जांच हुई।⁵⁶

सामाजिक न्याय

सफाईकर्मियों की सुरक्षा: सफाईकर्मियों के लिए शुरू की गई "नमस्ते योजना" में उन सभी लोगों को शामिल किया गया जो स्वच्छता के नेक दायित्व को निभाते हैं।

- सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जुलाई 2023 में नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (नमस्ते) योजना शुरू की गई थी।⁵⁷ इस योजना का उद्देश्य प्रशिक्षित और प्रमाणित सफाई कर्मचारियों के माध्यम से जोखिमपरक स्वच्छता की रोकथाम करना और सुरक्षित सफाई पद्धतियों को बढ़ावा देना है।⁵⁷ इसका उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपरक स्वच्छता में लगे व्यक्तियों को औपचारिक बनाना और उनका पुनर्वास करना भी है। यह योजना 350 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2025-26 तक चालू रहेगी।⁵⁷
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसार, 2019 से अक्टूबर 2025 के बीच सीवर और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपरक सफाई के कारण 471 सफाई कर्मचारियों की जान चली गई।⁵⁸ इस योजना के तहत सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: (i) सुरक्षा उपकरणों का वितरण, (ii) सफाई संबंधी मशीनरी की खरीद के लिए अग्रिम पूंजी सबसिडी, (iii) खतरों की रोकथाम पर व्यावसायिक प्रशिक्षण और कार्यशालाएं, (iv) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कवरेज।⁵⁹ सितंबर 2025 तक, इस योजना के तहत 88,448 सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों को मान्य किया जा चुका है।⁵⁷ मंत्रालय के अनुसार, जुलाई 2024 तक 766 जिलों में से 732 जिलों ने खुद को हाथ से मैला ढोने से मुक्त बताया है।⁶⁰
- जनवरी 2017 में सेल्फ-इंप्लॉयमेंट स्कीम फॉर रीहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स (एसआरएमएस) को शुरू किया गया था ताकि हाथ से मैला ढोने वाले चिन्हित मजदूरों और उनके आश्रितों के वैकल्पिक व्यवसायों में लगाने में मदद की जा सके।⁶¹ एसआरएमएस योजना को 2023-24 में नमस्ते योजना में समाहित कर लिया गया। एसआरएमएस के तहत, 58,098 मैला ढोने वालों को एकमुश्त नकद सहायता प्राप्त हुई।⁵⁸

ऋण तक पहुंची: दशकों तक सड़क किनारे सामान बेचकर जीवनयापन करने वाले हमारे भाई-साहब औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से वंचित रहे। आज वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित हो रहे हैं जिसके तहत वे अपने डिजिटल लेनदेन रिकॉर्ड के आधार पर अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

- स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना 2020 में शुरू की गई थी। 2025 तक इस योजना के तहत बिना गारंटी के 10,000 रुपए का वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता था। इसके बाद 20,000 रुपए और 50,000 रुपए के ऋण मिलने की सुविधा थी जिस पर सरकार की तरफ से ब्याज में 7% की सबसिडी दी जाती थी।⁶²

- अगस्त 2025 में, योजना का पुनर्गठन किया गया और इसे मार्च 2030 तक 7,332 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ बढ़ा दिया गया।⁶³ पुनर्गठित योजना का उद्देश्य 50 लाख नए लाभार्थियों सहित 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है।⁶³ नई ऋण संरचना के तहत, पहली किश्त के ऋण को 15,000 रुपए तक और दूसरी किश्त के ऋण को 25,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है।⁶³
- नवंबर 2025 तक पुनर्गठित योजना के तहत 79,396 नए लाभार्थियों को ऋण जारी किए गए हैं।⁶⁴ नवंबर 2025 तक 68 लाख स्ट्रीट वैंडर्स को 14,595 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान किए गए हैं।⁶⁴ लगभग 24.7 लाख स्ट्रीट वैंडर्स ने योजना के तहत दूसरा ऋण लिया है।⁶⁴
- पीएम स्वनिधि योजना के तहत, स्ट्रीट वैंडर्स को डिजिटल कैशबैंक प्रोत्साहन मिलता है। वे ऋण की प्रत्येक किश्त पर 12 महीनों के लिए प्रति माह 100 रुपए (प्रति वर्ष 1,200 रुपए) तक कमा सकते हैं।⁶⁵ पुनर्गठित योजना के तहत वे कम से कम 2,000 रुपए की डिजिटल थोक खरीदारी करने पर चार तिमाहियों तक प्रति तिमाही 100 रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं।⁶⁵ जून 2020 से 19 नवंबर 2025 तक लाभार्थियों को कैशबैंक के रूप में 242 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।⁶⁵

गरीबी कम करना: इन प्रयासों के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी से उबर चुके हैं और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं।

- गरीबी को मापने के लिए विभिन्न मापदंड हैं। गरीबी को आय स्तर के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। विश्व बैंक वैश्विक गरीबी रेखा को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 3 USD के रूप में परिभाषित करता है, जिसे अत्यधिक गरीबी भी कहा जाता है।⁶⁶ इस मापदंड के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली भारत की जनसंख्या का हिस्सा 2012 में 27.1% से घटकर 2021 में 5.3% हो गया।⁶⁶ हालांकि अधिकांश राज्यों में गरीबी में कमी आई है, लेकिन क्षेत्रीय भिन्नताएं भी हैं। 2022-23 में उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में गरीबी का स्तर सबसे अधिक था।⁶⁶ 2011-12 से 2022-23 तक निम्न-मध्यम आय वाले देशों की गरीबी रेखा (प्रति व्यक्ति प्रति दिन 4.2 USD) से नीचे रहने वाले लोगों का हिस्सा 57.7% से घटकर 23.9% हो गया।⁶⁶
- बहुआयामी गरीबी एक अन्य तरीका है जिसके जरिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता और आवास संबंधी अभावों का आकलन किया जा सकता है।⁶⁷ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार किया गया वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ऐसे 10 संकेतकों पर विचार करता है।⁶⁷ इसके अनुसार, भारत में 2015-16 (37 करोड़ बहुआयामी रूप से गरीब व्यक्ति) और 2020-21 (23 करोड़ बहुआयामी रूप से गरीब व्यक्ति) के बीच 14 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी से बाहर निकाला गया।⁶⁷ ये अनुमान क्रमशः 2015-16 और 2019-21 की अवधि में आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पर आधारित हैं।⁶⁷

तालिका 10: भारत की जनसंख्या का वह प्रतिशत जो बहुआयामी रूप से गरीब है

वर्ष	यूएनडीपी का बहुआयामी गरीबी सूचकांक	नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक
2005-06	55%	55%
2015-16	28%	25%
2019-21	16%	15%

स्रोत: 2005-06 से गरीब भारत में बहुआयामी गरीबी चर्चा पत्र, नीति आयोग, 2024; वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024, यूएनडीपी; पीआरएस।

- वैश्विक सूचकांक के समान, नीति आयोग ने एक राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक परिभाषित किया है।⁶⁸ यह सूचकांक वैश्विक सूचकांक में शामिल संकेतकों के अतिरिक्त दो और संकेतकों पर विचार करता है।⁶⁸ ये संकेतक मातृ स्वास्थ्य और बैंक खातों तक पहुंच से संबंधित हैं।⁶⁸ राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, 2015-16 और 2020-21 के बीच 13.5 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी से बाहर निकाला गया।⁶⁹ 2024 में, नीति आयोग द्वारा जारी एक चर्चा पत्र में अनुमान लगाया गया कि 2013-14 और 2022-23 के बीच नौ वर्षों में 24.8 करोड़ व्यक्तियों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया।⁶⁸ उसने 2015-16 और 2019-21 की अवधियों के लिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर ये अनुमान लगाए थे।⁶⁸

तालिका 11: भारत में गरीबी के बहुआयामी घटक, विश्व बैंक, 2022

बहुआयामी गरीबी घटक	जनसंख्या का %
प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 3 USD से कम का उपभोग	5.3%
किसी भी वयस्क ने प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं की है	13.8%
सीमित-मानक पेयजल उपलब्ध न होना	11.2%
सीमित-मानक स्वच्छता उपलब्ध न होना	29.9%
बिजली उपलब्ध न होना	1%

स्रोत: इंडिया पावर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ, विश्व बैंक, अक्टूबर 2025; पीआरएस।

श्रम

प्रशासन: केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना के तहत लाखों कर्मचारियों को 50% सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है जिसका व्यापक रूप से स्वागत किया गया है।

- एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है।⁷⁰ यूपीएस के तहत, 25 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पूर्व के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50% के निश्चित भुगतान के पात्र होते हैं। कम सेवा अवधि के लिए भुगतान आनुपातिक रूप से कम हो जाता है, जिसके लिए न्यूनतम अर्हता प्राप्त सेवा अवधि 10 वर्ष है।
- यूपीएस मार्च 2025 में लागू हुआ। यूपीएस का विकल्प चुनने की अवधि शुरू में जून 2025 तक थी जिसे बाद में सितंबर 2025 तक और फिर नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया। नवंबर 2025 तक 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों में से 1.2 लाख (5.2%) ने यूपीएस का विकल्प चुना है।⁷¹

तालिका 12: केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई विभिन्न पेंशन योजनाओं की विशेषताएं

विशेषताएं	ओपीएस (2003 तक)	एनपीएस (2004-2024)	यूपीएस (2025 से)
प्रकार	परिभाषित लाभ	परिभाषित अंशदान	परिभाषित लाभ और परिभाषित अंशदान, दोनों की विशेषताएं
फंडिंग	सरकारी राजस्व द्वारा वित्तपोषित	रोजगार की अवधि के आधार पर निर्मित सेवानिवृत्ति कोष से वित्त पोषित	सेवानिवृत्ति कोष से वित्त पोषित, सरकार सुनिश्चित पेंशन में किसी भी कमी को पूरा करेगी
कर्मचारी अंशदान	नहीं	हां	हां
पेंशन राशि	सुनिश्चित	कॉर्पस पर रिटर्न से जुड़ा हुआ	सुनिश्चित

स्रोत: राज्य सरकारों की पेंशन देनदारियों का अध्ययन करने वाले समूह की रिपोर्ट; प्रेस सूचना ब्यूरो; पीआरएस।

युवा रोजगार: मेरी सरकार ने युवाओं की शिक्षा और उनके लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया है।

- नई शिक्षा नीति (2020) में 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को 50% तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। 2021-22 में उच्च शिक्षा में नामांकन 28% था जो 2014-15 में 24% से अधिक था।⁷² तमिलनाडु (47%) और केरल (41%) जैसे राज्यों में उच्च शिक्षा में जीईआर अपेक्षाकृत अधिक था और बिहार (17%), झारखंड (19%) और उत्तर प्रदेश (24%) जैसे राज्यों में कम था।⁷² 2023-24 में उच्च माध्यमिक स्तर पर जीईआर 56% था जो प्राथमिक स्तर (93%) से काफी कम था।⁷³

तालिका 13: आईएलओ के अनुसार, 2024 में चयनित देशों में युवा बेरोजगारी दर (15-24 आयु वर्ग)

देश	युवा बेरोजगारी दर
भारत	16%
चीन	15%
युनाइटेड किंगडम	12%
युनाइटेड स्टेट्स	9%
रूस	9%
जर्मनी	7%

स्रोत: इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मॉडलड एस्टिमेंट्स डेटाबेस, 2024; पीआरएस।

- नवंबर 2025 में 15-29 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर 14.1% रही।⁷⁴ कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (2025) ने एक निजी अध्ययन का हवाला दिया और बताया कि भारत के सिर्फ 51% युवा ही रोजगार प्राप्त करने योग्य हैं।⁷⁵ युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं: (i) स्किल इंडिया मिशन, (ii) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, (iii) जन शिक्षण संस्थान, (iv) राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, और (v) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना।⁷⁵ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा के साथ एकीकृत करके कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।⁷⁶
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में स्नातक या उससे उच्च डिग्री धारकों की बेरोजगारी दर 2022 में 29% थी, जो 2000 में 24.5% थी।⁷⁷ रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में कार्यरत स्नातकों में से 53% कम कौशल वाली नौकरियों में लगे हुए थे। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, 2023-24 के अनुसार, स्नातक डिग्री धारकों की बेरोजगारी दर 12.1% थी।⁷⁸
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, 15-59 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों में से 27.4% ने व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया।⁷⁹ इनमें से केवल 3.8% ने औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- अगस्त 2025 में शुरू की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का लक्ष्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियां सृजित करना है।⁸⁰ इस योजना के तहत नव नियुक्त युवाओं को दो किस्तों में 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन और नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारी प्रति माह 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

तालिका 14: 15-29 आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर, 2023-24

वर्ष	ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण + शहरी		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
2023-24	5.6	9	6.5	6.2	13.3	7.9	5.9	10.6	7.1
2022-23	6	8.3	6.6	6.8	13.7	8.4	6.4	10.3	7.3
2021-22	7.5	10	8	8.2	14.3	9.5	7.8	11.8	8.6

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, 2023-24; पीआरएस।

इंटरनशिप: इंटरनशिप कार्यक्रम से एक करोड़ युवाओं को वास्तविक कार्य वातावरण में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त एक करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटरनशिप के अवसर दिए जाएंगे।

- प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना 2024-25 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटरनशिप के अवसर प्रदान करना है।⁸¹

- इस योजना के तहत अक्टूबर 2024 में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसका लक्ष्य उस वर्ष 1.25 लाख इंटरनेशिप के अवसर प्रदान करना था। पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में 8,700 (10.6%) उम्मीदवारों ने इंटरनेशिप के प्रस्ताव स्वीकार किए।⁸¹ इनमें से 4,565 (52%) उम्मीदवारों ने इंटरनेशिप पूरी होने से पहले ही छोड़ दी।⁸¹ दूसरे चरण में नवंबर 2025 तक, 2,053 (8%) उम्मीदवारों ने इंटरनेशिप पूरी किए बिना ही छोड़ दी।⁸¹ कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (2025) ने कम स्वीकृति और कम भागीदारी के निम्नलिखित कारणों पर प्रकाश डाला: (i) इंटरनेशिप का स्थान 5-10 किलोमीटर से अधिक दूर था, (ii) इंटरनेशिप की अवधि लंबी थी (12 महीने), और (iii) प्रस्तावित भूमिकाओं में रुचि की कमी थी।⁸¹

तालिका 15: प्रधानमंत्री इंटरनेशिप योजना के अंतर्गत पायलट परियोजनाओं की स्थिति, दिसंबर 2025 तक

पायलट प्रॉजेक्ट	विज्ञापित रिक्तियां	दिए गए प्रस्ताव	स्वीकृत किए गए प्रस्ताव		उम्मीदवार जिन्होंने छोड़ दिया	
चरण I	1.3 लाख	82,000	8,700	10.6%	4,565	52.5%
चरण II	1.2 लाख	83,000	24,600	29.6%	2,053	8.35%

स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 180, लोकसभा, 1 दिसंबर, 2025; पीआरएस।

पर्यावरण एवं ऊर्जा

अक्षय ऊर्जा: 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में पिछले छह महीनों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

- जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताएं:** 2030 तक भारत के निम्नलिखित लक्ष्य हैं: (i) 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा उत्पादन क्षमता, (ii) 2030 तक कुल स्थापित बिजली क्षमता का गैर-जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करना और (iv) 2030 तक अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% तक कम करना।^{82,83}
- नवंबर 2025 तक भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता 263 GW (52%) थी।⁸⁴ नवंबर 2025 तक उत्पादन में इसका योगदान लगभग 31% है **(तालिका 16)**।⁸⁵
- जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता, आर्थिक उत्पादन की प्रति इकाई पर होने वाले ग्रीनहाउस गैर उत्सर्जन को मापती है। भारत ने 2005 के स्तर की तुलना में 2020 में जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 36% तक कम कर दिया।⁸⁶

तालिका 16: स्रोत-वार स्थापित क्षमता और हिस्सा

स्रोत	स्थापित क्षमता नवंबर 2025 तक		अप्रैल से नवंबर 2025 तक का उत्पादन
	GW में	% हिस्सा	
कोयला	226	44%	68%
सौर ऊर्जा	133	26%	9%
जल ऊर्जा	50	10%	11%
पवन ऊर्जा	54	11%	7%
तेल और गैस	21	4%	1.6%
जैविक ऊर्जा	12	2%	0.5%
परमाणु ऊर्जा	9	2%	3%
लघु जल ऊर्जा	5	1%	0.7%
कुल	510	100%	100%

स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण; भारत का जलवायु और ऊर्जा डैशबोर्ड, 29 दिसंबर, 2025 को प्राप्त; पीआरएस।

- **ऊर्जा भंडारण:** पंप स्टोरेज प्लांट (पीएसपी) और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीएसई) जैसे स्टोरेज विकल्प दिन के समय या अनुकूल मौसम के दौरान अक्षय ऊर्जा को जमा करते हैं ताकि इसका उपयोग बिजली की अधिक मांग के समय और सूरज ढलने के बाद किया जा सके।⁸⁵ मार्च 2025 तक यह स्टोरेज क्षमता 5 से 5.5 GW के बीच थी।⁸⁵ विद्युत मंत्रालय (2023) के अनुसार, 2029-30 के लिए आवश्यक ऊर्जा भंडारण क्षमता 61 GW (19 GW पीएसपी और 42 GW बीएसई) होने की संभावना है।⁸⁷
- जून 2025 तक कुल 6.2 GW की स्थापित क्षमता वाले 10 सार्वजनिक सेवा प्रदाता संयंत्र (पीएसपी) चालू हो चुके हैं। 79 GW की क्षमता वाले अन्य 59 पीएसपी संयंत्र योजना और निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।⁸⁸

तालिका 17: प्रमुख देशों द्वारा कुल और प्रति व्यक्ति ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, 2024

देश	प्रति वर्ष दस लाख टन CO ₂ के बराबर ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन	प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ष CO ₂ के बराबर टन में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन
चीन	15,536	11
युनाइटेड किंगडम	5,913	17
भारत	4,371	3
रूस	2,576	18

स्रोत: एमिशन डेटाबेस फॉर ग्लोबल एटमॉस्फेरिक रिसर्च, यूरोपीय संघ, 2025; पीआरएस।

परमाणु ऊर्जा: हम परमाणु ऊर्जा के विस्तार के प्रयासों को भी तेज कर रहे हैं।

- वर्ष 2024-2025 में देश में कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 3.1% थी, जबकि कुल स्थापित परमाणु क्षमता 9 GW (1%) थी। परमाणु ऊर्जा विभाग (2025) के अनुसार, कुल उत्पादित बिजली की मात्रा के संदर्भ में परमाणु ऊर्जा की प्रति इकाई लागत सौर जैसे कुछ अक्षय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में भी कम है।⁸⁹ वर्ष 2023-24 में परमाणु ऊर्जा का औसत शुल्क 3.83 रुपए प्रति किलोवाट प्रति घंटा था।⁹⁰ परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार, 6.6 GW परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और 7 GW अतिरिक्त क्षमता को मंजूरी दी जा चुकी है।⁹¹
- केंद्रीय बजट 2025-26 में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) के विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई थी। इस मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं ताकि 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए और चालू एसएमआर विकसित किए जा सकें।⁹¹ इस मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 GW की क्षमता हासिल करना है।⁹¹
- दिसंबर 2025 में भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन और विकास (शांति) बिल, 2025 पारित किया गया।⁹² यह एक्ट परमाणु क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति देता है।

हरित हाइड्रोजन: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा और इससे 6 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे।

- हरित हाइड्रोजन का उत्पादन जीवाश्म ईंधन के बजाय सौर या पवन जैसे अक्षय स्रोतों से मिलने वाली बिजली का उपयोग करके पानी को विभाजित करके किया जाता है। भारतीय मानकों के अनुसार, इसे तब 'ग्रीन' माना जाता है, जब उत्सर्जन प्रति किलोग्राम उत्पादित हाइड्रोजन पर 2 किलोग्राम CO₂ समतुल्य से कम हो।⁹³ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है जिसके लिए लगभग 125 GW की अक्षय ऊर्जा क्षमता की आवश्यकता होगी।⁹³
- स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन (साइट) राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत एक योजना है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रोलाइजर्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में तेजी लाना है।⁹⁴

तालिका 18: नवंबर 2025 तक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत हुई प्रगति

घटक	प्रगति
साइट योजना के तहत इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण के लिए प्रोत्साहन	मई 2025 तक, इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण की कुल 3,000 MW प्रति वर्ष की क्षमता के लिए 15 कंपनियों को प्रोत्साहन राशि दी गई है। ⁹³
साइट योजना के तहत हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन	मई 2025 तक 19 कंपनियों को प्रति वर्ष 8.6 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता के लिए प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है। ⁹³
स्टील, शिपिंग और परिवहन क्षेत्रों में पायलट परियोजनाएं	मार्च 2025 तक, इस्पात निर्माण में हरित हाइड्रोजन के उपयोग के लिए तीन पायलट परियोजनाओं को 347 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 37 हाइड्रोजन-चालित वाहनों और 9 हाइड्रोजन रिफ्यूइंग स्टेशनों की स्थापना के लिए पांच पायलट परियोजनाओं को 208 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ⁹³
अनुसंधान और विकास	सुरक्षा और जैवमास आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 13 परियोजनाओं को ठेका दिया गया। ⁹⁵

स्रोत: संबंधित एंडनोट्स; पीआरएस।

रूफटॉप सोलर: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 75,000 करोड़ रुपये की लागत से रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। अब तक 75 लाख से अधिक घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं जिससे रोजगार के अनेक अवसर पैदा हुए हैं।

- प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) फरवरी 2024 में 75,021 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट के साथ शुरू की गई थी।⁹⁶ यह योजना 2026-27 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत आवासीय उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य एक करोड़ आवासीय रूफटॉप सोलर सिस्टम को प्रोत्साहित करके 2026-27 तक आवासीय क्षेत्र में 30 GW सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ना है।⁹⁶
- नवंबर 2025 तक 24.8 लाख घरों में सौर ऊर्जा लगाई जा चुकी है और 7.3 GW की रूफटॉप सौर क्षमता जोड़ी गई है।⁹⁷ प्राप्त 54 लाख आवेदनों में से लगभग 20 लाख इंस्टॉलेशन पूरे हो चुके हैं।⁹⁷
- ऊर्जा मंत्रालय (2025) ने धीमी प्रगति के लिए निम्नलिखित कारण बताए: (i) सरकारी भवनों का धीमा सौर ऊर्जाकरण, (ii) आवेदनों और वास्तविक स्थापनाओं के बीच अंतर, (iii) राज्यों और वितरण कंपनियों के भीतर अपर्याप्त समन्वय और क्षमता, और (iv) सीमित जन जागरूकता।⁹⁵

नदियों की इंटरलिंकिंग: 44,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली केन-बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों भाइयों और बहनों को लाभ मिलेगा।

- केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) का प्रस्ताव सबसे पहले 1980 में नदियों को जोड़ने के लिए तैयार की गई राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के अंतर्गत रखा गया था।⁹⁸ एनपीपी में देश भर में 30 नदियों की इंटरलिंकिंग परियोजनाओं की पहचान की गई थी। इन सभी 30 परियोजनाओं के लिए पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी हो चुकी हैं।⁹⁹
- केन-बेतवा लिंक परियोजना को राष्ट्रीय विकास परियोजना (एनपीपी) के तहत प्राथमिकता वाली परियोजना के रूप में नामित किया गया है।¹⁰⁰ इस परियोजना की अनुमानित लागत 44,605 करोड़ रुपये है। इसे 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन पूरा हो चुका है और परियोजना को पर्यावरण मंजूरी मिल चुकी है।⁹⁹ परियोजना के मुख्य अवसंरचना घटक, दौधन बांध का काम सौंपा जा चुका है और कार्यान्वयन गतिविधियां चल रही हैं।¹⁰⁰ जून 2025 तक परियोजना पर 11,329 करोड़ रुपये खर्च हो चुका है।⁹⁹

उद्योग

स्टार्टअप को प्रोत्साहन: भारत में अब 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं जो नवाचार के स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं।

- स्टार्ट-अप इंडिया योजना जनवरी 2016 में शुरू की गई थी।¹⁰¹ अक्टूबर 2025 तक सरकार द्वारा लगभग दो लाख स्टार्टअप को मान्यता दी गई है जिन्होंने खुद जानकारी दी कि इससे 21 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं।¹⁰² वाणिज्य से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2023) के अनुसार, स्टार्टअप मुख्य रूप से आईटी क्षेत्र में केंद्रित हैं, जबकि कृषि क्षेत्र में केवल 5% स्टार्टअप हैं।¹⁰⁶ अधिकांश स्टार्टअप टियर-1 शहरों में केंद्रित हैं। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का कहना है कि कि नवंबर 2025 तक 6,385 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप बंद हो चुके हैं।¹⁰³
- सितंबर 2025 तक भारत में 120 यूनिकॉर्न (एक अरब USD से अधिक मूल्य वाली) कंपनियां थीं जिनका संचयी मूल्यांकन 350 अरब USD था।¹⁰⁴
- स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता देने के लिए कई योजनाएं शामिल हैं। 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2030 के बीच स्थापित पात्र स्टार्टअप्स को उनके गठन के पहले 10 वर्षों में से किन्हीं भी लगातार तीन वर्षों के लिए लाभ पर 100% टैक्स की छूट दी जाती है।¹⁰⁵ वाणिज्य से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2023) का कहना था कि आयकर एक्ट, 1961 के तहत मिलने वाली इस छूट का उपयोग बहुत कम (10.4%) रहा है जिसका मुख्य कारण पात्रता के कड़े मानदंड और जटिल प्रक्रियाएं हैं।¹⁰⁶
- 2016 में सेबी-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश फंडों (एआईएफ) को पूंजी प्रदान करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना शुरू की गई थी जो बदले में बढ़ते भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं।¹⁰⁶ 2025 में सरकार ने स्टार्टअप्स 2.0 योजना के लिए फंड ऑफ फंड्स की घोषणा की।

तालिका 19: स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के तहत स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कार्यक्रम

योजना	उद्देश्य	कॉरपस	प्रगति
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना	स्टार्टअप्स को अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना	945 करोड़ रुपए	अक्टूबर 2025 तक इनक्यूबेटर्स ने 3,199 स्टार्टअप का चयन किया है और उन्हें 575 करोड़ रुपए की फंडिंग स्वीकृत की है।
स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना	अर्ली स्टेज, सीड स्टेज और ग्रोथ स्टेज के लिए पूंजी तक पहुंच	10,000 करोड़ रुपए	अक्टूबर 2025 तक, एआईएफ ने इस योजना के तहत 1,334 स्टार्टअप में 24,920 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना	योग्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्टार्टअप्स को बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराना	-	अक्टूबर 2025 तक, 755 करोड़ रुपए मूल्य के 311 ऋणों की गारंटी दी जा चुकी है

स्रोत: अतारंकित प्रश्न संख्या 1493, लोकसभा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 9 दिसंबर 2024; पीआरएस।

एमएसएमई: लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना और ई-कॉमर्स निर्यात केंद्रों की स्थापना से विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। इस तीसरे कार्यकाल के दौरान मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है जिससे करोड़ों लघु उद्यमियों को लाभ हुआ है।

- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएस) ऋण देने वाली सदस्य संस्थाओं को उन ऋणों के लिए गारंटी प्रदान करती है जो एमएसएमई को बिना किसी कोलेट्रल या थर्ड-पार्टी गारंटी के दिए जाते हैं।¹⁰⁷ प्रति उधारकर्ता यह गारंटी कवर 10 करोड़ रुपए तक है, जिसमें ऋण राशि का 75% से 90% तक का कवरेज शामिल है।¹⁰⁷

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) गैर-कृषि क्षेत्र में मैन्यूफैक्चरिंग, व्यापार या सेवा क्षेत्रों में कार्यरत आय सृजन करने वाले सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपए तक का सूक्ष्म ऋण प्रदान करती है जिसमें मुर्गी पालन, डेयरी और मधुमक्खी पालन शामिल हैं।¹⁰⁸ इस योजना में चार प्रकार के ऋण उत्पाद हैं: (i) 'शिशु' ऋण 50,000 रुपए तक, (ii) 'किशोर' ऋण 50,000 रुपए से अधिक और 5 लाख रुपए तक, (iii) 'तरुण' ऋण 5 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक, और (iv) 'तरुण प्लस' ऋण 10 लाख से 20 लाख रुपए के बीच।¹⁰⁸ तरुण प्लस ऋण श्रेणी को 25 अक्टूबर, 2024 को अधिसूचित किया गया था।¹⁰⁸

तालिका 20: सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट का प्रदर्शन

वर्ष	निर्माण		सेवा	
	स्वीकृत गारंटियों की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपए में)	स्वीकृत गारंटियों की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपए में)
2021-22	1,52,700	20,683	5,64,620	35,489
2022-23	2,59,022	35,338	9,06,764	69,444
2023-24	3,08,649	62,322	14,15,424	1,40,486
2024-25	14,15,424	1,40,486	13,74,937	1,42,275

स्रोत: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की अनुदान मांगों पर 127वीं रिपोर्ट, 2025-26; पीआरएस।

- 5 लाख से ऊपर की श्रेणियों में ऋण खातों की संख्या कम है, जिसमें तरुण श्रेणी कुल खातों का केवल 2.4% और तरुण प्लस केवल 0.01% है (तालिका 21)।

तालिका 21: वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पीएमएमवाई के तहत ऋण खातों की संख्या

ऋण के प्रकार	शिशु	किशोर	तरुण	तरुण प्लस
ऋण का आकार	50,000 रुपए तक	50,000 और 5 लाख रुपए के बीच	5 लाख और 10 लाख रुपए के बीच	10 लाख और 20 लाख रुपए के बीच
खातों की संख्या	19,43,49,221	8,70,91,055	68,09,128	30,427

स्रोत: अतारंकित प्रश्न संख्या 2322, वित्त मंत्रालय, 15 दिसंबर, 2025; पीआरएस।

स्क्रेपिंग: मेरी सरकार ने पुराने वाहनों के वैज्ञानिक निपटान को सुनिश्चित करने के लिए वाहन स्क्रेपिंग नीति लागू की है जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

- वाहन स्क्रेपिंग नीति का उद्देश्य पुराने और अनुपयुक्त वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। इसके लिए ऐसे प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने हेतु प्रोत्साहन/निरुत्साहन की व्यवस्था की गई है।¹⁰⁹ दिसंबर 2025 तक देश में 188 पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग केंद्र काम कर रहे हैं जिन्होंने स्क्रेपिंग के लिए 1.3 लाख प्रमाणपत्र जारी किए हैं।¹¹⁰

सहकारी समितियां: हमारी 8 लाख सहकारी समितियां और उनके 29 करोड़ सदस्य, ग्रामीण भारत के लगभग 90% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- नवंबर 2025 तक देश में 30 क्षेत्रों में 8.4 लाख सहकारी समितियां हैं।¹¹¹ आवास क्षेत्र में सहकारी समितियों की संख्या सबसे अधिक (1.9 लाख) है, इसके बाद डेयरी समितियां (1.6 लाख) और प्राथमिक कृषि समितियां (1 लाख) हैं।¹¹¹
- प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पीएसीएस) किसानों को ऋण प्रदान करती हैं। दिसंबर 2025 तक 2.6 लाख ग्राम पंचायतें पीएसीएस के अंतर्गत आती हैं।¹¹² पीएसीएस को निम्नलिखित कार्यों के लिए भी सक्षम बनाया गया है: (i) प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो किसानों को एक ही स्थान पर उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि सामग्री उपलब्ध कराते हैं, (ii) साझा सेवा केंद्र जो बैंकिंग, बीमा, बिजली बिल भुगतान, स्वास्थ्य और कानूनी सेवाओं जैसी ई-सेवाएं प्रदान करते हैं, और (iii) प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र जो किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराते हैं।¹¹³

स्वास्थ्य

सस्ती दवाएं: जन औषधि केंद्रों में 80% रियायती दरों पर दवाएं उपलब्ध कराने से नागरिकों की 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। समाज के हर वर्ग को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नागरिकों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए देश भर में 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं।

- जन औषधि योजना का उद्देश्य जन औषधि केंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं किफायती दामों पर उपलब्ध कराना है।¹¹⁴ इन फार्मसियों को उनकी मासिक दवा खरीद पर 20% की दर से प्रोत्साहन राशि मिलती है।¹¹⁴ यह प्रोत्साहन राशि अधिकतम 20,000 रुपए प्रति माह निर्धारित की गई है।¹¹⁴ सितंबर 2024 से मासिक प्रोत्साहन राशि को 200 दवाओं के स्टॉक रखने की अनिवार्यता से जोड़ दिया गया है।¹¹⁵
- सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 25,000 करना है।¹¹⁶ दिसंबर 2025 तक 17,610 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं।¹¹⁶ 2020-21 और 2024-2025 के बीच जन औषधि केंद्रों के माध्यम से 6,290 करोड़ रुपए की दवाओं की बिक्री हुई है।¹¹⁷
- आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) उन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जो समुदायों के निकट निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, पुनर्वास और उपशामक सेवाएं प्रदान करते हैं। दिसंबर 2025 तक 1.8 लाख एएएम काम कर रहे हैं।¹¹⁸
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सरकारी अस्पतालों और केंद्रों (एएएम सहित) की जांच करता है। यह जांच 2022 के भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के आधार पर वहां के बुनियादी ढांचे, कर्मचारियों और सुविधाओं को लेकर की जाती है।¹¹⁹ 22 जनवरी, 2025 तक 93% केंद्रों का मूल्यांकन किया जा चुका था, जिनमें से केवल 55% केंद्र ही 50% मानकों पर खरे उतरे।¹¹⁹

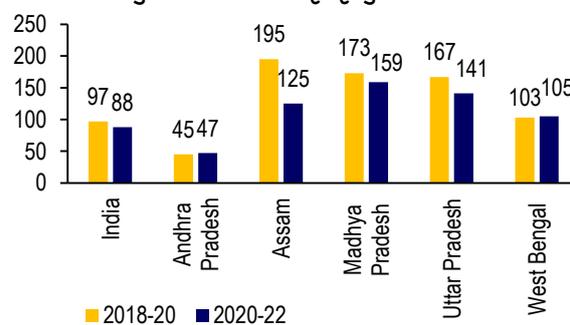
मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य: भारत में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रमों की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए U-WIN पोर्टल शुरू किया गया है। अब तक इस प्लेटफॉर्म पर लगभग 30 करोड़ टीके का रिकॉर्ड दर्ज किया जा चुका है।

- मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) गर्भावस्था या प्रसव संबंधी जटिलताओं के कारण प्रति एक लाख बच्चों के जन्म पर माताओं की मृत्यु को दर्शाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य 2026 तक एमएमआर को घटाकर 87 करना है।¹²⁰ भारत में एमएमआर 2018-20 में 97 से घटकर 2020-22 में 88 हो गया है।¹²¹ विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, 2023 में वैश्विक एमएमआर 197 था।¹²²

- 2020-22 में मध्य प्रदेश (159) में सबसे अधिक मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) थी जबकि केरल (18) में सबसे कम थी।¹²³ आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों में एमएमआर में वृद्धि देखी गई है।¹²³

- सरकार गर्भवती महिलाओं को मुफ्त प्रसव उपलब्ध कराने के लिए जननी सुरक्षा योजना लागू कर रही है।¹²⁴ इस योजना का उद्देश्य अस्पतालों में प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करना है। अस्पतालों में होने वाले जन्मों की संख्या 2015-16 में 79% थी जो 2019-21 में बढ़कर 89% हो गई है।¹²⁵

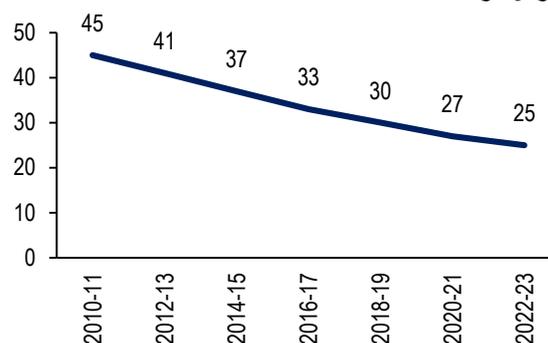
रेखाचित्र 12: कुछ राज्यों में मातृ मृत्यु दर



स्रोत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2023, भारत में मातृ मृत्यु दर पर बुलेटिन 2020-22; पीआरएस।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया को कम करना है।¹²⁶ हालांकि 2015-16 और 2019-21 के बीच महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की समस्या बढ़ी है। 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया की समस्या 2015-16 में 53% से बढ़कर 2019-21 में 57% हो गई है।¹²⁷

रेखाचित्र 13: भारत में प्रति 1,000 जन्म पर शिशु मृत्यु दर



स्रोत: विश्व बैंक, 12 जनवरी 2026 को एक्सेस किया गया; पीआरएस।

- वर्ष 2023 तक भारत में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) प्रति हजार जीवित जन्मों पर 25 थी।¹²⁸ उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आईएमआर सबसे अधिक 37 थी जबकि मणिपुर में यह सबसे कम 3 थी।¹²⁸
- नवजात मृत्यु दर (एनएमआर) का अर्थ है, हर 1,000 जीवित शिशुओं के जन्म पर, जन्म के पहले 28 दिनों के भीतर, कितने शिशुओं की मृत्यु हुई।¹²⁹ सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत भारत का लक्ष्य 2030 तक एनएमआर को घटाकर 12 करना है। युनाइटेड नेशंस मेटरनल मॉरटैलिटी एस्टिमेशन इंटर-एजेंसी ग्रुप के अनुसार, 2023 में भारत की नवजात मृत्यु दर 17 थी जो 2000 में 45 थी।¹²⁹ भारत ने पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 70% और नवजात मृत्यु दर में 61% की गिरावट हासिल की।¹²⁹
- U-WIN एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को 12 बीमारियों से बचाने के लिए दिए जाने वाले सभी टीकों के डिजिटलीकरण का काम करता है।¹³⁰ यूआईपी का लक्ष्य प्रतिवर्ष 3 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 2.7 करोड़ नवजात शिशुओं को टीका लगाना है।¹³¹ नवंबर 2024 तक U-WIN ने 7.4 करोड़ लाभार्थियों को पंजीकृत किया था और 27.8 करोड़ टीके लगाए जा चुके थे।¹³⁰
- 2023-24 तक राष्ट्रीय टीकाकरण कवरेज 93.5% है।¹³² नागालैंड (60%), सिक्किम (65%) और राजस्थान (77%) जैसे कई राज्यों में टीकाकरण कवरेज कम है।¹³²

स्वास्थ्य बीमा: आयुष्मान भारत योजना के तहत, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य कवर के साथ स्वास्थ्य बीमा प्राप्त होगा।

- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध है।^{133,134} यह योजना 12 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों (लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों) को लाभ पहुंचाती है। दिसंबर 2025 तक 42.7 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं।¹³⁵ इन कार्ड्स की मदद से लोग 10 करोड़ बार अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करवा चुके हैं।¹³⁵
- अक्टूबर 2024 में सरकार ने एबी-पीएमजेएवाई योजना का विस्तार 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों तक कर दिया।¹³⁶ इससे छह करोड़ नागरिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दिसंबर 2025 तक वरिष्ठ नागरिकों को 93 लाख कार्ड जारी किए जा चुके हैं।¹³⁶ अक्टूबर 2025 तक वरिष्ठ नागरिकों के अस्पताल में भर्ती होने के कुल 7.9 लाख मामलों को मंजूरी दी गई जिनकी लागत 1,741 करोड़ रुपए है।¹³⁶ केंद्रीय बजट भाषण 2025-26 में इस योजना का विस्तार करके प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स को भी इसमें शामिल करने की योजना का उल्लेख किया गया है।¹³⁷
- कैंग (2023) ने पाया कि कई राज्यों में सूचीबद्ध अस्पतालों में बुनियादी ढांचे, उपकरणों और डॉक्टरों की कमी थी।¹³⁸ कुछ उपकरण काम नहीं कर रहे थे।¹³⁸ उसमें यह भी पाया कि अस्पताल में भर्ती के लिए पूर्व-अनुमोदन के 3.6 करोड़ दावों में से 40 लाख (11%) दावों को 12 घंटे की निर्धारित समय सीमा से अधिक समय

लगा।¹³⁸ स्वास्थ्य से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने पाया कि योजना का दायरा सीमित है क्योंकि बाह्य रोगी देखभाल (ओपीडी), निवारक स्वास्थ्य देखभाल और अस्पताल में बिना भर्ती हुए होने वाले खर्च इसमें शामिल नहीं हैं।¹³⁹ कमिटी ने कैंसर जैसी लंबी अवधि के उपचार वाली बीमारियों के लिए भी कवरेज बढ़ाने का सुझाव दिया।¹³⁹

- कैंग (2022) के अनुसार, इस योजना के तहत कुल 3.6 करोड़ दावों का निपटारा किया जा चुका है जिनकी राशि 42,434 करोड़ रुपए है।¹⁴⁰ नवंबर 2022 तक 40 लाख दावों पर अंतिम निर्णय (मंजूरी या अस्वीकृति) की प्रक्रिया चल रही थी जिनकी राशि 6,052 करोड़ रुपए थी।¹³⁸ पीएम-जेएवाई दिशानिर्देशों के तहत, पूर्व-अनुमति को 6 घंटे के भीतर स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। अगर किसी पूछताछ या जानकारी की जरूरत हो तो इसे 12 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि कैंग (2022) के अनुसार, 39.6 लाख दावों को पूर्व-अनुमति प्राप्त करने में 12 घंटे से अधिक का समय लगा।¹⁴⁰
- 5 अगस्त 2023 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के दिशानिर्देशों के अनुसार, एसएचए ने कुल 1.6 लाख दावों के खिलाफ उचित कार्रवाई की है। इसके अलावा कदाचार में संलिप्तता के कारण 210 अस्पतालों को पैनल से हटा दिया गया है और 188 अस्पतालों को निलंबित कर दिया गया है।

मेडिकल कॉलेज की स्थापना: सरकार अगले पांच वर्षों में मेडिकल कॉलेजों में 75,000 नई सीटें बनाने पर भी काम कर रही है।

- भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2013-14 में 387 से बढ़कर दिसंबर 2025 में 818 हो गई।^{141,142} 2025-26 तक मेडिकल शिक्षा की क्षमता लगभग 1.29 लाख स्नातक सीटों और 80,291 स्नातकोत्तर सीटों की है।¹⁴²
- स्वास्थ्य से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2024) ने कहा था कि कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में प्रति दस लाख जनसंख्या पर लगभग 150 एमबीबीएस सीटें थीं, जबकि अन्य राज्यों में प्रति दस लाख जनसंख्या पर 50 से कम सीटें थीं। उदाहरण के लिए बिहार में प्रति दस लाख जनसंख्या पर केवल 21 सीटें थीं।¹⁴³

तालिका 22: 2014-15 से 2025-26 तक मेडिकल कॉलेजों और सीटों में वृद्धि

मेडिकल कॉलेज और सीट	2013-14	2025-26
मेडिकल कॉलेजों की संख्या	387	818
अंडरग्रेजुएट सीटों की संख्या	51,348	1,28,875
पोस्टग्रेजुएट सीटों की संख्या	31,185	80,291

स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 1034, लोकसभा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 5 दिसंबर, 2025; पीआरएस।

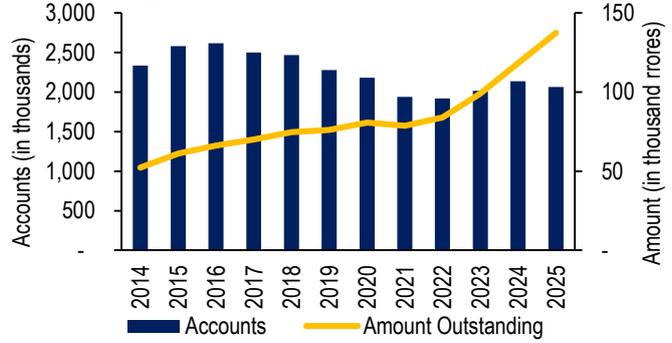
- सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य और केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों और स्वतंत्र स्नातकोत्तर संस्थानों को सुदृढ़ और उन्नत बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तीसरे चरण को मंजूरी दी।¹⁴⁴ यह चरण 2025-26 से 2028-29 तक चलेगा और इसका उद्देश्य 5,000 स्नातकोत्तर सीटें और 5,023 एमबीबीएस सीटें जोड़ना है जिसमें प्रति सीट लागत की अधिकतम सीमा 1.5 करोड़ रुपए है।¹⁴⁴
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों में एम्स की स्थापना करना है। दिसंबर 2025 तक 22 एम्स की स्थापना को मंजूरी दी जा चुकी है।¹⁴⁵ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (2025) के अनुसार, चालू हो चुके 20 एम्स में 2025-26 में फैकेल्टी के 40% से अधिक पद खाली हैं।¹⁴⁶
- सरकार 2023-24 और 2026-27 के बीच 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की एक योजना को लागू कर रही है।¹⁴⁷ इनमें से 113 नर्सिंग कॉलेजों को अब तक मंजूरी मिल चुकी है।¹⁴⁷

शिक्षा

उच्च शिक्षा के लिए सहायता: मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की गई है।

- प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना को नवंबर 2024 में सीमित वित्तीय संसाधनों वाले विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।¹⁴⁸ इस योजना के तहत शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थानों में योग्यता के आधार पर प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान किए जाते हैं।
- दिसंबर 2025 तक इस योजना के तहत 5.56 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे।¹⁴⁹ लगभग 1.98 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं जिनकी कुल राशि 5,786 करोड़ रुपए है।¹⁴⁹

रेखाचित्र 14: पिछले एक दशक में उच्च शिक्षा ऋण की कुल बकाया राशि में वृद्धि हुई है



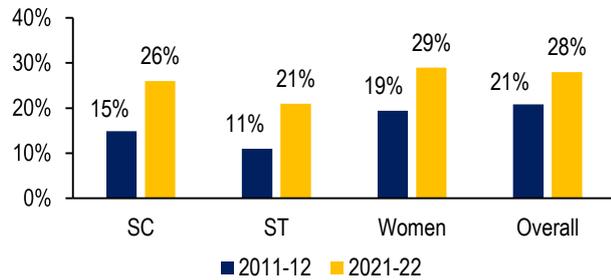
स्रोत: शिक्षा से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी की 372 वीं रिपोर्ट, राज्यसभा, 9 दिसंबर, 2025; पीआरएस।

- शिक्षा समिति (2025) ने स्वीकृत ऋणों के वितरण में देरी पर गौर किया था।¹⁵⁰ उसने कहा था कि फरवरी से अगस्त 2025 के बीच योजना के तहत स्वीकृत किए गए ऋणों में से केवल 15% का ही वितरण किया गया था।¹⁵⁰ कमिटी ने आगे यह भी कहा कि हालांकि 2014 और 2025 के बीच सक्रिय विद्यार्थी ऋणों की संख्या में गिरावट आई है, लेकिन कुल ऋण राशि में तेजी से वृद्धि हुई है।¹⁵⁰

उच्च शिक्षण संस्थान: पिछले एक दशक में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और उनकी गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग में 163 भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। विभिन्न विषयों में शिक्षा के लिए सीटों की संख्या में कई गुना वृद्धि से मध्यम वर्ग को काफी लाभ हुआ है।

- उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 2021-22 में 28.4% था, जो 2011-12 के स्तर (21%) से अधिक है (रेखाचित्र 15)।⁵
- 2014 से अब तक सात आईआईटी, आठ आईआईएम और 16 आईआईआईटी स्थापित किए जा चुके हैं।¹⁵¹ अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, भारत में 1,168 विश्वविद्यालय, 45,473 कॉलेज और लगभग 12,000 स्वतंत्र संस्थान थे।¹⁵²

रेखाचित्र 15: 2011-12 से उच्च शिक्षा में नामांकन में वृद्धि हुई है



स्रोत: अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2011-2 और 2021-22; पीआरएस।

- हालांकि इनमें से कई संस्थानों में महत्वपूर्ण रिक्तियां हैं। मार्च 2025 तक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण पदों में 29% रिक्तियां थीं (स्वीकृत पदों की तुलना में)।¹⁵³ गैर-शिक्षण पदों में 48% रिक्तियां थीं।¹⁵³
- 2020-21 में भारत के अनुसंधान व्यय में विश्वविद्यालयों की हिस्सेदारी 9% थी।¹⁵⁴ भारत से 54 विश्वविद्यालयों को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शामिल किया गया है, जिसमें 1,500 से अधिक

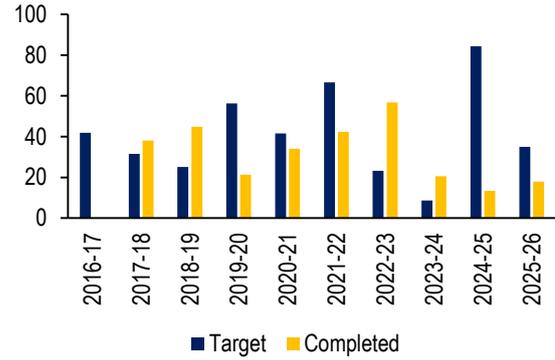
विश्वविद्यालयों को स्थान दिया गया है।¹⁵⁵ क्यूएस वर्ल्ड एशिया रैंकिंग 2024 में 294 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया था।¹⁵⁶ भारत से रैंकिंग प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या 2015 में 11 से बढ़कर 54 हो गई है। सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले आईआईटी दिल्ली को 123वां स्थान मिला, जबकि आईआईटी बॉम्बे को 129वां स्थान प्राप्त हुआ।¹⁵⁵

ग्रामीण एवं शहरी विकास

सस्ते आवास: प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए हमने अतिरिक्त तीन करोड़ परिवारों को नए घर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।

- प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) और शहरी (पीएमएवाई-यू) क्षेत्रों में कुछ समूहों को सस्ते आवास तक पहुंच प्रदान करना है।
- शुरुआत में इन योजनाओं को 2022 तक ही चलना था¹⁵⁷ लेकिन इन्हें 2028-29 तक बढ़ा दिया गया है।^{157,158,159} इस समय सीमा को बढ़ाने से पिछले चरणों के बचे हुए घरों को पूरा किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण इलाकों में दो करोड़ नए घर बनाए जाएंगे, जिनमें उन गरीब परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनका नाम पुरानी लिस्ट (सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना की प्रतीक्षा सूची) में रह गया है।¹⁵⁷

रेखाचित्र 16: पीएमएवाई-जी के तहत लक्षित और निर्मित घरों की संख्या (लाख में)



स्रोत: पीएमएवाई-जी डैशबोर्ड, 28 दिसंबर, 2025 को एक्सेस किया गया; पीआरएस।

- पीएमएवाई-जी के तहत, 4.15 करोड़ घरों के कुल लक्ष्य (सभी चरणों सहित) के मुकाबले, दिसंबर 2025 तक कुल 2.89 करोड़ (70%) घर पूरे हो चुके हैं।¹⁶⁰
- पीएमएवाई-यू योजना के तहत, मंत्रालय का लक्ष्य शहरी गरीबों को 2.18 करोड़ घर उपलब्ध कराना है। जनवरी 2026 तक 1.22 करोड़ घरों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से 96.65 लाख (79%) घर पूरे हो चुके हैं।¹⁶¹ अगस्त 2024 में मंत्रिमंडल ने पीएमएवाई-यू 2.0 को मंजूरी दी जिसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए एक करोड़ घरों का निर्माण करना है।¹⁶²

ग्रामीण रोजगार: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, देशभर में 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सशक्त बनाया जा रहा है, जिससे 10 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ रही हैं। इन समूहों को बैंक लिंक के जरिए 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है।

- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का उद्देश्य गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता और रोजगार के अवसर प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करना है।¹⁶³ यह योजना स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के जरिए परिवारों को संगठित करने और ऋण एवं वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाने का प्रयास करती है। सामुदायिक संसाधनों को मजबूत करने के लिए, सरकार एकमुश्त (i) प्रत्येक एसएचजी को 20,000 रुपए से 30,000 रुपए तक का रिवॉल्विंग फंड और (ii) एसएचजी संघों के जरिए से 2.5 लाख रुपए तक का सामुदायिक निवेश कोष प्रदान करती है।¹⁶⁴
- जून 2025 तक इस कार्यक्रम के तहत 91 लाख स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जा चुका था, जिसमें 10 करोड़ से अधिक परिवारों ने भाग लिया था।¹⁶⁵ दिसंबर 2024 तक स्वयं सहायता समूहों द्वारा 10.9 लाख करोड़ रुपए का बैंक ऋण लिया जा चुका था।¹⁶⁵

- एनआरएलएम के दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना घटक का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों के युवाओं को रोजगार से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। 2016 से जून 2025 के बीच, इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित 17.5 लाख लोगों में से 11.5 लाख (66%) को रोजगार मिल चुका है।¹⁶⁵
- ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान एक बैंक-संचालित कार्यक्रम है, जिसके तहत प्रायोजक बैंक अपने-अपने जिलों में कौशल और उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, वर्ष 2009 से जून 2025 तक 56.7 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और 41 लाख उम्मीदवारों को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है।¹⁶⁵

सड़क से कनेक्टिविटी: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत, सरकार ने 25,000 बस्तियों को जोड़ने के लिए 70,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।

- ग्रामीण क्षेत्रों में खराब कनेक्टिविटी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) शुरू की।¹⁶⁶ इस योजना के तहत सभी पात्र ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जा रहा है।
- दिसंबर 2025 तक योजना के तहत स्वीकृत 8,36,446 किमी सड़क लंबाई में से 94% सड़कें पूरी हो चुकी हैं (तालिका 23)।¹⁶⁷ पीएम-जनमन योजना के तहत, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों द्वारा बसे क्षेत्रों को लक्षित करती है, स्वीकृत सड़कों में से केवल 16% ही पूरी हुई हैं।^{167,167}
- पीएमजीएसवाई-IV परियोजना सितंबर 2024 में 62,500 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के उद्देश्य से शुरू की गई थी।¹⁶⁸ इसे 2024-2029 के लिए लागू किया गया है।
- मार्च 2024 और जनवरी 2025 के बीच राष्ट्रीय क्वालिटी मॉनिटर्स ने रखरखाव कार्य का निरीक्षण किया। 1,228 सड़कों में से 257 सड़कें (21%) असंतोषजनक पाई गईं।¹⁶⁹ इसी अवधि के दौरान, राज्य के क्वालिटी मॉनिटर्स ने जिन 13,824 सड़कों का निरीक्षण किया, उनमें से 2,423 सड़कें (18%) असंतोषजनक पाई गईं।¹⁶⁹

तालिका 23: पीएमजीएसवाई के विभिन्न विभागों के अंतर्गत स्वीकृत और पूर्ण की गई सड़कों की लंबाई (किलोमीटर में)

खंड	स्वीकृत	पूर्ण	पूर्णता का %
पीएमजीएसवाई-I	6,44,735	6,25,097	97%
पीएमजीएसवाई -II	49,795	49,086	99%
पीएमजीएसवाई -III	1,22,388	1,02,444	84%
आरसीपीएल डब्ल्यूईए	12,212	9,892	81%
जनमन	7,316	1,176	16%
कुल	8,36,446	7,87,695	94%

स्रोत: पीएमजीएसवाई डैशबोर्ड, ग्रामीण विकास मंत्रालय, 28 दिसंबर, 2025 को एक्सेस किया गया; पीआरएस।

संपत्ति का स्वामित्व: स्वामित्व योजना के तहत हमने अब तक 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड जारी किए हैं, जिनमें से लगभग 70 लाख संपत्ति कार्ड अकेले पिछले छह महीनों में वितरित किए गए हैं।

- अप्रैल 2020 में शुरू की गई स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों के संपत्ति मालिकों और किसानों को अधिकारों का रिकॉर्ड (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) प्रदान करना है। दिसंबर 2025 तक 1.8 लाख गांवों के लिए 2.8 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।¹⁷⁰ लगभग 3 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।¹⁷¹

सुरक्षा एवं रणनीतिक मामले

आंतरिक सुरक्षा: वामपंथी अतिवाद को खत्म करने का अंतिम चरण भी शुरू हो चुका है। सरकार के प्रयासों के चलते वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर आज 38 रह गई है।

- वामपंथी अतिवाद (एलडब्ल्यूई) से संबंधित घटनाओं की संख्या 2010 में 1,936 से घटकर 2025 में 222 रह गई, जो 89% की गिरावट है।¹⁷² इसी प्रकार नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौतों में भी 91% की कमी आई है जो 2010 में 1,005 से घटकर 2025 में 95 रह गई।¹⁷²
- प्रभावित जिलों की संख्या 2014 में 10 राज्यों के 126 जिलों से घटकर 2025 में पांच राज्यों के 11 जिले रह गई है।¹⁷² इनमें से केवल तीन जिलों को वर्तमान में सबसे अधिक एलडब्ल्यूई प्रभावित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।¹⁷² सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के तहत, एलडब्ल्यूई के प्रभाव को फिर से उभरने से रोकने के लिए नौ राज्यों के 27 जिलों को 'लिंगेसी और थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट्स' के रूप में कवर किया जा रहा है।¹⁷²

तालिका 14: एलडब्ल्यूई गतिविधियों के खिलाफ अभियान के तहत प्रगति

वर्ष	मारे गए एलडब्ल्यूईज	गिरफ्तार किए गए एलडब्ल्यूईज	संरंद्ध करने वाले एलडब्ल्यूईज
2020	103	1,110	475
2021	126	1,153	736
2022	57	816	496
2023	50	924	376
2024	290	1,090	881
2025*	335	942	2,167

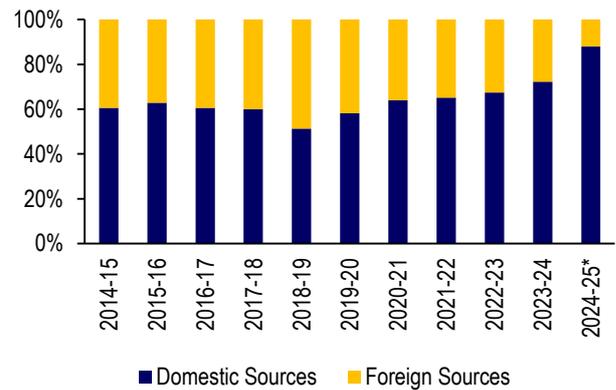
* 1 दिसंबर, 2025 तक के आंकड़े।

स्रोत: अतारंकित प्रश्न संख्या 2682, लोकसभा, गृह मामलों का मंत्रालय, 16 दिसंबर, 2025; पीआरएस।

रक्षा निर्माण: हमने विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में अत्यंत उत्साहजनक परिणाम प्राप्त किए हैं।

- भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पादन 2014-15 में 46,429 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 1.54 लाख करोड़ रुपए हो गया।¹⁷³ रक्षा निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत 74% तक और सरकारी मार्ग के तहत 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी है।¹⁷⁴
- रक्षा निर्यात 2014 में 1,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपए हो गया।¹⁷⁵ यह वृद्धि मुख्य रूप से निजी कंपनियों द्वारा रक्षा निर्यात में हुई बढ़ोतरी के कारण हुई है। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए और 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात हासिल करना है।¹⁷⁵
- एसआईपीआरआई के आंकड़ों के अनुसार, भारत 2020 और 2024 के बीच की अवधि में हथियारों का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक था, जो वैश्विक आयात का 8.3% हिस्सा था।¹⁷⁶
- 2023-24 में, पूंजी अधिग्रहण व्यय का 28% विदेशी स्रोतों से खरीद पर खर्च किया गया था।¹⁷⁷
- रक्षा उत्कृष्टता नवाचार योजना 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 498 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लागू की जा रही है।¹⁷⁸ यह योजना रक्षा नवाचार परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए

रेखाचित्र 17: रक्षा आधुनिकीकरण व्यय में घरेलू और विदेशी स्रोतों की हिस्सेदारी



* दिसंबर, 2024 तक के आंकड़े।

स्रोत: 93वाँ रिपोर्ट, रक्षा संबंधी स्टैंडिंग कमिटी, मार्च; पीआरएस।

स्टार्टअप/एमएसएमई को 1.5 करोड़ रुपए तक का अनुदान प्रदान करेगी।¹⁷⁸ सितंबर 2025 तक लगभग 3,250 करोड़ रुपए के 50 उत्पादों की खरीद के लिए मंजूरी प्राप्त हो चुकी है, और 36 उत्पादों के लिए 1,652 करोड़ रुपए के खरीद आदेश दिए गए हैं।¹⁷⁹

विज्ञान एवं तकनीक

अनुसंधान और नवाचार: ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और यह 76वें स्थान से 39वें स्थान पर पहुंच गया है। शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उद्देश्य भारत को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी देशों में स्थान दिलाना है।

- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार, भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाओं में 38वें स्थान पर है।¹⁸⁰ ये वे देश हैं जो नवाचार इनपुट (संस्थान, मानव पूंजी, बुनियादी ढांचा आदि) और आउटपुट (ज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि) दोनों में सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन करते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा रिपोर्ट 2023 के अनुसार, बौद्धिक संपदा संबंधी दस्तावेजों के मामले में भारत छठे स्थान पर है।¹⁸⁰ शोध प्रकाशनों के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है।¹⁸⁰ वैज्ञानिक प्रकाशनों की संख्या 2018 में 1.3 लाख से बढ़कर 2022 में 2.1 लाख हो गई है।¹⁸¹
- अनुसंधान विकास एवं नवाचार योजना नवंबर 2025 में एक लाख करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू की गई थी।¹⁸² इस योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र के नेतृत्व में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है और यह ऊर्जा सुरक्षा एवं संक्रमण, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों को लक्षित करती है।
- राष्ट्रीय क्वांटम मिशन मार्च 2023 में शुरू किया गया था और इसे आठ वर्षों तक 6,004 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया जाएगा।¹⁸² इस मिशन के तहत, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी, क्वांटम मैटीरियल और उपकरण और क्वांटम संचार में प्रौद्योगिकी विकास का समर्थन करने के लिए चार केंद्र स्थापित किए गए हैं। नवंबर 2025 तक जारी किए गए 468.2 करोड़ रुपए में से 68.3 करोड़ रुपए (14.6%) का उपयोग किया जा चुका है।¹⁸³
- अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना फरवरी 2024 में हुई थी।¹⁸² इसका उद्देश्य वैज्ञानिक विषयों में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को समर्थन प्रदान करना, अनुसंधान और विकास को मजबूत करना और भारत के शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देना है।¹⁸² मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई-इंपैक्ट एरियाज़ पहल के तहत एनआरएफ ने अब तक चार मिशन शुरू किए हैं: (i) इलेक्ट्रिक वाहन मिशन, (ii) 2डी इनोवेशन हब, (iii) मेडटेक मिशन, और (iv) विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए एआई पहल।¹⁸² 2024-25 में एनआरएफ को 966 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिनमें से 721 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया था।¹⁸⁴

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: इंडिया एआई मिशन के शुभारंभ के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के योगदान को और अधिक महत्व दिया जा रहा है।

- भारत में एआई मिशन मार्च 2024 में शुरू किया गया था जिसका बजट पांच वर्षों के लिए 10,372 करोड़ रुपए था।¹⁸⁵ निम्नलिखित तालिका 25 योजना के सात घटकों की प्रगति का संक्षिप्त विवरण प्रदान करती है।

तालिका 15: इंडिया एआई मिशन के सात घटकों के तहत प्रगति

घटक	लक्ष्य	जुलाई 2025 तक प्रगति
इंडिया एआई कंप्यूट	हाई-एंड ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (जीपीयू) को सस्ती कीमतों पर देना	38,000 से अधिक जीपीयू को शामिल किया जा चुका है और ये इंडियाएआई कंप्यूट पोर्टल पर 65 रुपए प्रति घंटे की दर से उपलब्ध हैं।
इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर	स्वास्थ्य सेवा, कृषि, जलवायु परिवर्तन, गवर्नेंस और सहायक शिक्षण प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में भारत-विशिष्ट चुनौतियों के लिए एआई एप्लिकेशंस को विकसित करना।	जुलाई 2025 तक 30 आवेदनों को मंजूरी दी जा चुकी है।
इंडियन एआई डेटासेट प्लेटफॉर्म	एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए बड़े डेटासेट विकसित करना।	20 क्षेत्रों में 3,000 से अधिक डेटासेट और 243 एआई मॉडल उपलब्ध हैं।
इंडिया एआई एप्लिकेशन डेवलपमेंट इनीशिएटिव	भारतीय डेटा और भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए भारत के अपने बड़े मल्टीमोडल मॉडल विकसित करना।	पहले चरण में 500 आवेदनों में से चार स्टार्टअप्स को मंजूरी दी गई है।
इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स	एआई-स्किल्ड प्रोफेशनल्स को विकसित करना।	500 पीएचडी फेलो, 5,000 स्नातकोत्तर और 8,000 स्नातक विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की जा रही है। जुलाई 2025 तक 200 से अधिक विद्यार्थियों को फेलोशिप प्राप्त हुई। 26 संस्थानों ने पीएचडी विद्यार्थियों को दाखिला दिया।
इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनांसिंग	एआई स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना।	इस मिशन ने 10 भारतीय स्टार्टअप्स को यूरोपीय बाजार में विस्तार करने में मदद की।
सेफ एंड ट्रस्टेड एआई	मजबूत गवर्नेंस के साथ जिम्मेदार एआई एडॉप्शन सुनिश्चित करना।	पहले दौर में आठ परियोजनाओं का चयन किया गया। दूसरे दौर में 400 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए।

स्रोत: "ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विद एआई" प्रेस सूचना ब्यूरो मुख्यालय, 12 अक्टूबर 2025; पीआरएस।

नैसकॉम (2024) की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि भारत में एआई टैलेंट बेस की संख्या 2027 तक लगभग 6.5 लाख से बढ़कर 12.5 लाख से अधिक होने की उम्मीद है।¹⁸⁵ मंत्रालय ने एआई सहित 10 नई और उभरती प्रौद्योगिकियों में आईटी पेशवरों के कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए फ्यूचरस्किल्स प्राइम कार्यक्रम शुरू किया है। अगस्त 2025 तक 3.4 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक अपने पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं।¹⁸⁵ मंत्रालय ने अनुसार, अगस्त 2025 तक लगभग 3.2 लाख उम्मीदवारों ने एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स पाठ्यक्रमों में नामांकन किया है।¹⁸⁵

साइबर सुरक्षा: सरकार ने साइबर खतरों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं जिससे युवाओं के लिए साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारत ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर-1 का दर्जा हासिल कर लिया है।

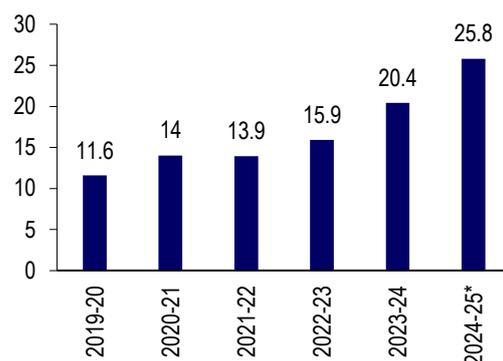
- इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन यूनियन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल साइबरसिक्योरिटी इंडेक्स, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रयासों का आकलन पांच क्षेत्रों में करता है: कानूनी, तकनीकी, संगठनात्मक, क्षमता विकास और सहयोग।¹⁸⁶ 2024 में भारत ने टियर-1 का दर्जा प्राप्त किया।¹⁸⁶
- सूचना सुरक्षा शिक्षा एवं जागरूकता परियोजना को 2023 से पांच वर्षों के लिए 333 करोड़ रुपए के बजट के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है।¹⁸⁷ इस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई पहलों में शामिल हैं: (i) साइबर सुरक्षा खतरों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र, (ii) दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम्स का पता लगाने और उन्हें हटाने के टूल्स के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र, और (iii) साइबर सुरक्षा पेशवरों को एआई सिस्टम्स से जुड़े कौशल से लैस करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रमाणित सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स नामक विशेष कार्यक्रम।¹⁸⁷

तालिका 16: वर्ष 2018-22 के दौरान दर्ज किए गए साइबर अपराध और दोषी ठहराया जाना

वर्ष	दर्ज होने वाले साइबर अपराध	दोषी ठहराए गए
2018	27,248	495
2019	44,735	367
2020	50,035	1,110
2021	52,974	491
2022	65,893	1,118

स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 4482, लोकसभा, सूचना एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय, 20 अगस्त, 2025; पीआरएस।

रेखाचित्र 18: साइबर सुरक्षा संबंधी दर्ज घटनाओं की संख्या (लाखों में)



* आंकड़े अक्टूबर 2025 तक के हैं।

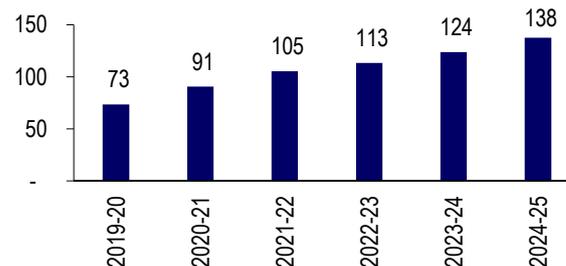
स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 2297, राज्यसभा, सूचना एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय, 19 दिसंबर 2025; पीआरएस।

आदिवासी मामले

लगभग 1.25 लाख आदिवासी बच्चों को 470 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो रही है।

- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) योजना का उद्देश्य कक्षा VI से XII तक के आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।¹⁸⁸
- इस योजना का उद्देश्य 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक जनजातीय प्रबंधन केंद्र (ईएमआरएस) स्थापित करना है।¹⁸⁹ 2011 की जनगणना के अनुसार, ऐसे 564 उप-जिले हैं।¹⁸⁹ जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 2026 तक देश भर में 728 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अगस्त 2025 तक 722 ईएमआरएस स्वीकृत किए जा चुके हैं जिनमें से 478 कार्यरत हैं और 235 निर्माणाधीन हैं।¹⁸⁸

रेखाचित्र 19: वर्षवार ईएमआरएस में नामांकन (हजारों में)



स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 3265, लोकसभा, आदिवासी मामलों का मंत्रालय, 20 मार्च, 2025; पीआरएस।

¹ Address by the President of India to the Joint Sitting of two houses of Parliament, Office of the President of India, January 31, 2025, <https://presidentofindia.nic.in/sites/default/files/2023-06/sp31012025eng.pdf>.

² GDP at current prices (USD), International Monetary Fund, <https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD>.

³ First Advanced Estimates of Gross Domestic Product, 2025-26, Press Information Bureau, Ministry of Statistics & Programme Implementation, January 7, 2026, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2212087®=3&lang=1>.

⁴ Payment Systems India, June 2025, Reserve Bank of India, <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/PAYMENTSYSTEM23102025AFCA907BFE9749C78225BB58B43211FA.PDF>.

⁵ India's UPI revolution, Press Information Bureau, July 20, 2025, <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154912&ModuleId=3®=3&lang=2>.

⁶ 11 Years of PM Jan Dhan Yojana: Banking the Unbanked, Press Information Bureau, August 27, 2025, <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=155102&ModuleId=3®=3&lang=2>.

⁷ Unstarred question no 20, Ministry of Finance, Lok Sabha, December 1, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU20_ZAwvpe.pdf?source=pqals.

- ⁸ The Central Goods and Services Tax Act, 2017, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2017/Central%20GST%20Act.%202017.pdf.
- ⁹ “Recommendations of the 56th Meeting of the GST Council held at New Delhi today”, Press Information Bureau, Ministry of Finance, September 3, 2025, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2163555>.
- ¹⁰ Volume-I, Report of the 15th Finance Commission for 2021-26, February 2021, https://fincomindia.nic.in/writereaddata/html_en_files/fincom15/Reports/XVFC%20VOL%20I%20Main%20Report.pdf.
- ¹¹ Final Estimate of Production of Food Grains for 2024 25, Department of Agriculture and Farmers' Welfare, 2025, <https://agriwelfare.gov.in/en/AgricultureEstimates>.
- ¹² Volume 8, Production Enhancement through Productivity Gains, Report of the Committee on Doubling Farmers' Income, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, February 2018, <https://agriwelfare.gov.in/Documents/DFI%20Vol-8A.pdf>
- ¹³ Volume 14, Comprehensive Policy Recommendations, Report of the Committee on Doubling Farmers' Income, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, September 2018, https://agriwelfare.gov.in/Documents/DFI_Volume_14.pdf
- ¹⁴ Unstarred Question No. 398, Lok Sabha, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, February 4, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU398_h9RqVn.pdf?source=pqals.
- ¹⁵ Starred Question No. 101, Lok Sabha, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, July 20, 2024, https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/2977765/1/AS101_Zv2zbg.pdf.
- ¹⁶ “Agricultural Infrastructure Fund (AIF) Scheme” Press Information Bureau, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, August 28, 2024, <https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2024/aug/doc2024828382201.pdf>.
- ¹⁷ Agriculture Infrastructure Fund Dashboard, as accessed on December 22, 2025, <https://agriinfra.dac.gov.in/>.
- ¹⁸ Study to determine post-harvest losses of agri produces in India, NABARD Consultancy Services, Ministry of Food Processing Industries, December 7, 2022, https://www.mofpi.gov.in/sites/default/files/phl_study_final_report_07.12.2022_2.pdf
- ¹⁹ “Launch of National Mission on Natural Farming”, Press Information Bureau, Cabinet, November 25, 2024, <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2077094>.
- ²⁰ “National Mission on Natural Farming” Press Information Bureau, Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare, August 13, 2025, <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=155019&ModuleId=3®=3&lang=2>.
- ²¹ Unstarred Question No 3909, Lok Sabha, Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare, August 12, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU3909_xNFwZE.pdf?source=pqals.
- ²² National Mission on Natural Farming website, as accessed on December 22, 2025, <https://naturalfarming.dac.gov.in/>.
- ²³ The National Food Security Act, 2013, <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2113/1/201320.pdf>.
- ²⁴ “Serving Farmers and Saving Farming” Fifth Report, National Commission on Farmers, October 4, 2006, <https://agriwelfare.gov.in/sites/default/files/NCF5%20Vol.-1%20%281%29.pdf>.
- ²⁵ Unstarred Question No. 3553, “Uniform MSP for Foodgrain” Lok Sabha, Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare, December 17, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU3553_cRjHa9.pdf?source=pqals.
- ²⁶ https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU2963_jEU5QS.pdf?source=pqals&utm_source=chatgpt.com.
- ²⁷ “Empowering Farmers through PM-AAASHA”, Press Information Bureau, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, December 18, 2024, <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2085530#>.
- ²⁸ India's Mission for Atmanirbharta in Pulses, Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare, October 11, 2025, <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?id=155497&NoteId=155497&ModuleId=3>.
- ²⁹ Unstarred Question No 2553, Lok Sabha, DA&FW, December 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU2553_TzaQfm.pdf?source=pqals.
- ³⁰ “Deendayal Antyodaya Yojana- National Rural Livelihoods Mission” Press Information Bureau, October 23, 2025, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2181702®=3&lang=2>.
- ³¹ Unstarred Question No. 3619, “Lakhpati DIDI” Lok Sabha, Ministry of Rural Development, December 17, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU3619_ViZSvH.pdf?source=pqals.
- ³² Unstarred Question No 4237, Lok Sabha, Ministry of Rural Development, August 19, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4237_xppm40.pdf?source=pqals.
- ³³ “NAMO Drone Didi Scheme” Press Information Bureau, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, December 17, 2024, <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2085177>.
- ³⁴ Unstarred Question No. 3536, “NAMO Drone Didi Scheme” Lok Sabha, Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare, December 17, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU3536_OWpDJ0.pdf?source=pqals.
- ³⁵ Unstarred Question No 3804, Lok Sabha, Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare, August 12, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU3804_TTVJvn.pdf?source=pqals.
- ³⁶ Unstarred Question No. 3572, “Categorisation of Farmers Under KISAN SAMMAN Pension Scheme” Lok Sabha, Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare, December 17, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU3572_uJEE74.pdf?source=pqals.
- ³⁷ Unstarred Question No 358, Lok Sabha, Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare, December 2, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU358_FPeZsZ.pdf?source=pqals.
- ³⁸ “India's Dairy Sector”, Press Information Bureau, September 29, 2025, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2172546®=3&lang=2>.
- ³⁹ Basic Animal Husbandry Statistics 2025, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying, 2025, <https://dahd.gov.in/sites/default/files/2025-12/BasicAnimalHusbandryStatistics2025.pdf>
- ⁴⁰ “Productivity of Dairy Animals” Press Information Bureau, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying, March 24, 2021, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1707187®=3&lang=2>.
- ⁴¹ “Strategies and Pathways for Accelerating Growth in Pulses towards the Goal of Atmanirbharta” NITI Aayog, 2025, <https://niti.gov.in/sites/default/files/2025-09/Strategies-and-Pathways-for-Accelerating-Growth-in-Pulses-towards-the-Goal-of-Atmanirbharta.pdf>.
- ⁴² Starred Question No. 301, “Average income of farmers” Lok Sabha, Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare, December 17, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AS301_DNVhhc.pdf?source=pqals.
- ⁴³ “Income, Expenditure, Productive Assets and Indebtedness of Agricultural Households in India” NSS Round 70th, 2013, https://mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/nss_rep_576.pdf.
- ⁴⁴ “Land and livestock holdings of Households and Situation Assessment of Agricultural Households” NSS Round 77th, Ministry of Statistics and Programme Implementation, 2019, https://mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/Report_587m_0.pdf.
- ⁴⁵ “Ministry of Railways: Year End Review 2025” Press Information Bureau, Ministry of Railways, December 28, 2026, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2209199®=3&lang=1#:~:text=Between%201%20April%20and%2030.total%20renewal%20works%20were%20done>.

- ⁴⁶ “Union Minister Ashwini Vaishnaw Inspects Vande Bharat Sleeper Train at New Delhi Railway Station” Press Information Bureau, Ministry of Railways, January 3, 2026, <https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2211160®=3&lang=2#:~:text=The%20first%20Vande%20Bharat%20Sleeper,train%20has%20been%20successfully%20concluded.>
- ⁴⁷ Budget at a Glance, 2025-26, Ministry of Finance, https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_at_Glance/budget_at_a_glance.pdf.
- ⁴⁸ “Implementation of e-buses scheme” Press Information Bureau, Ministry of Heavy Industries, December 6, 2024, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2081560&utm_source=chatgpt.com®=3&lang=2.
- ⁴⁹ PM e-Bus Sewa-Payment Security Mechanism (PSM) Scheme, Ministry of Heavy Industries website, as accessed on January 7, 2025, <https://heavyindustries.gov.in/en/pm-e-bus-sewa-payment-security-mechanism-psm-scheme>.
- ⁵⁰ Unstarred Question No 2042, Lok Sabha, Ministry of Housing and Urban Affairs, December 11, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU2042_xeTLJP.pdf?source=pqals.
- ⁵¹ Unstarred Question No 3110, Lok Sabha, Ministry of Housing and Urban Affairs, December 18, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU3110_fno4Dx.pdf?source=pqals.
- ⁵² Economic Survey 2025, Ministry of Finance, <https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf>.
- ⁵³ Starred Question No 266, Lok Sabha, Ministry of Civil Aviation, December 18, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AS266_NbgHSS.pdf?source=pqals.
- ⁵⁴ Unstarred Question No 1631, Rajya Sabha, Ministry of Civil Aviation, December 15, 2025, https://sansad.in/getFile/annex/269/AU1631_1DB20L.pdf?source=pqars.
- ⁵⁵ Niti Aayog website, as accessed on January 7, 2026, <https://niti.gov.in/aspirational-districts-programme>.
- ⁵⁶ Champions of Change Dashboard, NITI Aayog, as accessed on January 7, 2026, <https://championsofchange.gov.in/dashboard?activeTab=2>.
- ⁵⁷ “National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem (NAMASTE)” Press Information Bureau, September 10, 2025, <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=155183&ModuleId=3®=3&lang=2>.
- ⁵⁸ Unstarred Question No 2615, Lok Sabha, Ministry of Social Justice and Empowerment, December 16, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU2615_xMOYye.pdf?source=pqals.
- ⁵⁹ Unstarred Question No 265, Lok Sabha, Ministry of Social Justice and Empowerment, December 2, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU265_gc5xEc.pdf?source=pqals.
- ⁶⁰ “Manual scavenging” Press Information Bureau, Ministry of Social Justice & Empowerment, August 2024, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2042007®=3&lang=2>.
- ⁶¹ Self-Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers, MyScheme Dashboard, <https://www.myscheme.gov.in/schemes/srms>.
- ⁶² Scheme Dashboard, SVANidhi Scheme, as accessed on January 7, 2026, <https://www.myscheme.gov.in/schemes/pm-svanidhi>.
- ⁶³ “SVANidhi: Empowering Street Vendors” Press Information Bureau, Ministry of Social Welfare, December 20, 2025, <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=156604&ModuleId=3®=3&lang=1>.
- ⁶⁴ Unstarred Question No 3180, Lok Sabha, Ministry of Housing and Urban Affairs, December 18, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU3180_h2tv0Y.pdf?source=pqals.
- ⁶⁵ Unstarred Question No 3010, Lok Sabha, Ministry of Housing and Urban Affairs, December 18, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU3010_uAj8qs.pdf?source=pqals.
- ⁶⁶ World Bank Poverty and Equity Brief, India, October 2025, <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099722104222534584/pdf/IDU-25f34333-d3a3-44ae-8268-86830e3bc5a5.pdf>.
- ⁶⁷ Global Multidimensional Poverty Index 2025, United Nations Development Programme, <https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/mpireport2025en.pdf>.
- ⁶⁸ Multidimensional Poverty in India since 2005-06, Discussion Paper, NITI Aayog, United Nations Development Programme, January 12, 2024, https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2024-01/MPI-22_NITI-Aayog20254.pdf.
- ⁶⁹ National Multidimensional Poverty Index, India, A Progress Review, NITI Aayog, 2023, <https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-08/India-National-Multidimensional-Poverty-Index-2023.pdf>.
- ⁷⁰ Starred Question No 111, Lok Sabha, Ministry of Finance, July 28, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AS111_6YSNsp.pdf?source=pqals.
- ⁷¹ Unstarred Question No 2389, Lok Sabha, Ministry of Finance, December 15, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU2389_yt3DdE.pdf?source=pqals.
- ⁷² All India Survey of Higher Education 2021-22, <https://cdnbbsr.s3.waas.gov.in/s392049debb566ca5782a3045cf300a3c/uploads/2025/06/2025060466438560.pdf>.
- ⁷³ Unified District Information System for School Education 2023-24, Ministry of Education, https://api.udiseplus.gov.in/udisefms/api/fileUpload/getDocument/DCF2021/UDISE_Report_2023_24_Existing_Structure.pdf.
- ⁷⁴ Periodic Labour Force Survey, Monthly Bulletin, November 2025, Ministry of Statistics and Programme Implementation, https://www.mospi.gov.in/uploads/publications_reports/publications_reports/1765793969210_4cc3881d-7905-494b-90a3-cbecc6afacfb_PLFS_Monthly_Bulletin_November_2025_15122025.pdf.
- ⁷⁵ “Unemployability and Skill Training In Rural Regions” Press Information Bureau, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, July 23, 2025, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147366®=3&lang=2>.
- ⁷⁶ National Education Policy (NEP) 2020, Ministry of Education, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf.
- ⁷⁷ “India Employment Report 2024: Youth employment, education and skills”, International Labour Organisation, https://www.ilo.org/sites/default/files/2024-08/India%20Employment%20-%20web_8%20April.pdf.
- ⁷⁸ Periodic Labour Force Survey 2023-24, Ministry of Statistics and Programme Implementation, https://dge.gov.in/dge/sites/default/files/2024-10/Annual_Report_Periodic_Labour_Force_Survey_23_24.pdf.
- ⁷⁹ Periodic Labour Force Survey 2022-23, Ministry of Statistics and Programme Implementation, https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/AR_PLFS_2022_23N.pdf.
- ⁸⁰ “PM Modi Announces Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana to Boost Youth Employment,” Press Information Bureau, Ministry of Labour & Employment, August 15, 2025, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2156794®=3&lang=2>.
- ⁸¹ Unstarred Question No 180, Lok Sabha, Ministry of Corporate Affairs, December 1, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU180_M3YLHb.pdf?source=pqals.
- ⁸² National Statement by Prime Minister Shri Narendra Modi at COP26 Summit in Glasgow, Ministry of External Affairs, November 21, 2021, <https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/34466/National+Statement+by+Prime+Minister+Shri+Narendra+Modi+at+COP26+Summit+in+Glasgow>.
- ⁸³ Unstarred Question No 1,285, Lok Sabha, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, December 8, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU1285_t38BKS.pdf?source=pqals.

- ⁸⁴ India Energy Climate Dashboard, NITI Aayog, as accessed on December 15, 2025, <https://iced.niti.gov.in/energy/electricity/generation/capacity>.
- ⁸⁵ Fifth report of the Standing Committee on Energy, Ministry of New and Renewable Energy, March 2025, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Energy/18_Energy_5.pdf?source=loksabhadocs.
- ⁸⁶ "India submits its 4th Biennial Update Report to the United Nations Framework Convention on Climate Change" Press Information Bureau, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, January 2, 2025, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2089589®=3&lang=2>
- ⁸⁷ National Framework for Promoting Energy Storage Systems, Ministry of Power, August 2023, https://powermin.gov.in/sites/default/files/National_Framework_for_promoting_Energy_Storage_Systems_August_2023.pdf
- ⁸⁸ "Progress of Hydro Pumped Storage Projects," Press Information Bureau, Ministry of Power, July 28, 2025, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2149363®=3&lang=2>.
- ⁸⁹ "Nuclear Power Myths and Facts" Department of Atomic Energy, accessed on December 22, 2025, <https://dae.gov.in/nuclear-power-myths-and-facts/#1673945863316-e38bb595-bde3>.
- ⁹⁰ Starred Question No 226, Lok Sabha, department of Atomic Energy, December 11, 2024, <https://cdnbbsr.s3.waas.gov.in/s35b8e4fd39d9786228649a8a8bec4e008/uploads/2024/12/20241216687736722.pdf>.
- ⁹¹ Starred Question No 251, Department of Atomic Energy, Lok Sabha, December 17, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AS251_O8dFdY.pdf?source=pqals.
- ⁹² Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Act, 2025, https://prsindia.org/files/bills/acts/bills_parliament/2025/Sustainable_Harnessing_and_Advancement%20of_Nuclear_Energy_Bill.2025.pdf.
- ⁹³ "Unlocking India's Green Hydrogen Production Potential" Press Information Bureau, November 12, 2025, <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?id=155990&NoteId=155990&ModuleId=3®=3&lang=2>
- ⁹⁴ SIGHT scheme guidelines, Ministry of New and Renewable Energy, January, 2024, <https://cdnbbsr.s3.waas.gov.in/s3716e1b8c6cd17b771da77391355749f3/uploads/2024/01/202401161382200321.pdf>.
- ⁹⁵ Fifth report of the Standing Committee on Energy, Ministry of New and Renewable Energy, March 2025, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Energy/18_Energy_5.pdf?source=loksabhadocs.
- ⁹⁶ Press Information Bureau "Cabinet approves PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana for installing rooftop solar in One Crore households", <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2010133>.
- ⁹⁷ PM-Surya Ghar Dashboard, as accessed on December 22, 2025, <https://pmsuryaghar.gov.in/#/state-ut-wise-progress>
- ⁹⁸ National Perspective Plan, National Water Development Agency, 1980, [https://nwda.gov.in/upload/uploadfiles/files/NATIONAL%20PERSPECTIVE\(1\).pdf](https://nwda.gov.in/upload/uploadfiles/files/NATIONAL%20PERSPECTIVE(1).pdf).
- ⁹⁹ Unstarred Question No 2479, Rajya Sabha, Ministry of Jal Shakti, August 11, 2025, https://sansad.in/getFile/annex/268/AU2479_R3r3b5.pdf?source=pqars.
- ¹⁰⁰ "Interlinking of Rivers Progress, Clearances and Funding" Press Information Bureau, Ministry of Jal Shakti, December 15, 2025, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2204097>.
- ¹⁰¹ About Startup India, Startup India, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, <https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/about-startup-india-initiative.html>.
- ¹⁰² Unstarred Question No 1648, Lok Sabha, Ministry of Science and Technology, December 10, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU1648_DvTLpz.pdf?source=pqals.
- ¹⁰³ Unstarred Question No 698, Rajya Sabha, Ministry of Commerce and Industry, December 5, 2025, https://sansad.in/getFile/annex/269/AU698_N66MJ6.pdf?source=pqars
- ¹⁰⁴ "Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah, inaugurates Startup Conclave 2025 in Gandhinagar, Gujarat" Press Information Bureau, Ministry of Home Affairs, September 23, 2025, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2170168®=3&lang=2>.
- ¹⁰⁵ Finance Bill, 2025, India Budget, https://www.indiabudget.gov.in/doc/Finance_Bill.pdf.
- ¹⁰⁶ Report 182, Standing Committee on Commerce, Rajya Sabha, August 2023, https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/13/174/182_2024_1_10.pdf?source=rajyasabha.
- ¹⁰⁷ Unstarred Question No 4698, Lok Sabha, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, August 21, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4698_zu0VRQ.pdf?source=pqals
- ¹⁰⁸ Unstarred Question No 1179, Lok Sabha, Ministry of Finance, December 8, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU1179_NA7CA5.pdf?source=pqals
- ¹⁰⁹ Unstarred Question No 465, Lok Sabha, Ministry of Road Transport and Highways, July 25, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/182/AU465_zahDD3.pdf?source=pqals
- ¹¹⁰ Registered Vehicle Scrapping Facility Dashboard, Ministry of Road Transport and Highways, accessed on December 24, 2025, <https://vscrap.parivahan.gov.in/vehiclescrap/vahan/dashboard.xhtml>.
- ¹¹¹ Unstarred Question No 1500, Lok Sabha, Ministry of Cooperation, December 9, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU1500_Wwh3dT.pdf?source=pqals.
- ¹¹² "PACS, dairy, fisheries and multi-purpose cooperatives in Odisha" Press Information Bureau, Ministry of Cooperation, December 17, 2025, <https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2205540®=3&lang=2>
- ¹¹³ "Expansion and Diversification of PACS" Press Information Bureau, Ministry of Cooperation, December 9, 2025, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2201663®=3&lang=2>.
- ¹¹⁴ "Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana" (PMBJP), Department of Pharmaceuticals Ministry of Chemicals and Fertilisers, <https://pharmaceuticals.gov.in/sites/default/files/Website%20update%202022%20PMBJP-1.pdf>.
- ¹¹⁵ PMBI/06/Circular/74/2024-25, Circular by Pharmaceuticals & Medical Devices Bureau of India, August 29, 2024, https://janaushadhi.gov.in/pdf/Circular%20Removal%20and%20Enhancement_30082024.pdf.
- ¹¹⁶ "Target set to increase the number of Jan Aushadhi Kendras to 25,000 by March 2027," Press Information Bureau, Ministry of Chemicals and Fertilizers, December 16, 2025, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2204607®=3&lang=2>.
- ¹¹⁷ Unstarred Question No 2080, Lok Sabha, Ministry of Chemicals and Fertilizers, December 12, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU2080_OQ8Bpt.pdf?source=pqals.
- ¹¹⁸ Arogya Ayushman Mandir Dashboard, Ministry of Health and Family Welfare, as accessed on December 28, 2025, <https://aam.mohfw.gov.in/>.
- ¹¹⁹ "Measures taken to Strengthen Public Healthcare Facilities," Press Information Bureau, Ministry of Health and Family Welfare, February 7, 2025, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2100597&utm_source=chatgpt.com®=3&lang=2.
- ¹²⁰ Unstarred Question No. 712, Ministry of Health and Family Welfare, Lok Sabha, February 7, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU712_5G3btK.pdf?source=pqals

- ¹²¹ Special Bulletin on Maternal Mortality In India 2020-22, Sample Registration System, June 2025, https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog/45569/download/49766/SRS_MMR_Bulletin_2020_2022.pdf
- ¹²² Trends in maternal mortality 2000 to 2023, World Health Organisation, <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/29f43a3d-2228-489c-b1e7-b2f28e9101ce/content>.
- ¹²³ National Health Profile, 2023, Ministry of Health and Family Welfare, December 2025, <https://cbhidghs.mohfw.gov.in/sites/default/files/NHP/NHP-2023-Last-Final.pdf>.
- ¹²⁴ MyScheme Portal, Janani Suraksha Yojana, accessed on December 23, 2025, <https://www.myscheme.gov.in/schemes/jsy1>
- ¹²⁵ “Saving Mothers, Strengthening Futures”, Press Information Bureau, March 2025, <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154004&ModuleId=3®=3&lang=2>
- ¹²⁶ “Union Cabinet informed about progress under National Health Mission (NHM) - 2020-21”, Ministry of Health and Family Welfare, Press Information Bureau, September 28, 2022, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1862938>.
- ¹²⁷ National Family Health Survey, 2019-21, <https://www.nfhsiips.in/nfhsuser/nfhs5.php>.
- ¹²⁸ Sample Registration System Bulletin, Volume 58, No 1, September 2025, https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog/46178/download/50426/SRS_Bulletin_2023_Vol_58_No_1.pdf
- ¹²⁹ Levels & Trends in Child Mortality Report 2024, United Nations Maternal Mortality Estimation Inter-Agency Group, 2025, https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2025/05/UNIGME-2024-Child-Mortality-Report_13-May.pdf
- ¹³⁰ “Update on U WIN Portal,” Press Information Bureau, Ministry of Health and Family Welfare, November 2024, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2079025®=3&lang=2>
- ¹³¹ Universal Immunisation Program, Ministry of Health and Family Welfare, <https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Universal%20Immunization%20Programme.pdf>
- ¹³² “Update on Immunization of Children,” Press Information Bureau, Ministry of Health and Family Welfare, August 2024, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2042058&utm_source=chatgpt.com®=3&lang=2.
- ¹³³ “About Ayushman Bharat”, Ministry of Health and Family Welfare, as accessed on January 7, 2025, <https://nha.gov.in/PM-JAY#>.
- ¹³⁴ Unstarred Question No. 2534, “Status of AB-PMJAY and ABDM in Tamil Nadu”, Ministry of Health and Family Welfare, Rajya Sabha, December 17, 2024, https://sansad.in/getFile/annex/266/AU2534_ezNoMA.pdf?source=pqars.
- ¹³⁵ Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana Dashboard, as accessed on January 7, 2025, National Health Authority, Ministry of Health and Family Welfare, <https://dashboard.nha.gov.in/public/>.
- ¹³⁶ Unstarred Question No. 2188, Lok Sabha, Ministry of Health and Family Welfare, December 12, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU2188_kak82B.pdf?source=pqals.
- ¹³⁷ Speech of the Finance Minister, Budget 2025-26, https://www.indiabudget.gov.in/doc/budget_speech.docx.
- ¹³⁸ Report No. 11: Performance Audit of Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, Comptroller and Auditor General of India, August 8, 2023, <https://cag.gov.in/en/audit-report/details/119060>.
- ¹³⁹ Report No. 151: Implementation of Ayushman Bharat”, Standing Committee on Health and Family Welfare, December 19, 2023, https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/14/187/151_2023_12_19.pdf?source=rajyasabha.
- ¹⁴⁰ Performance Audit of Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, CAG, 2023, https://cag.gov.in/uploads/download_audit_report/2023/Report-No.-11-of-2023_PA-on-PMJAY_English-PDF-A-064d22bab2b83b5.38721048.pdf.
- ¹⁴¹ “India Expands Medical Education” Press Information Bureau, Ministry of Health and Family Welfare, September 27, 2025, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2172069>.
- ¹⁴² Unstarred Question No. 1034, Lok Sabha, Ministry of Health and Family Welfare, December 5, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU1034_c0ICms.pdf?source=pqals.
- ¹⁴³ One hundred Fifty Seventh Report of the Parliamentary Standing Committee on “Quality of Medical Education in India”, Rajya Sabha, February 2024, https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/14/187/157_2024_2_19.pdf?source=rajyasabha.
- ¹⁴⁴ “Cabinet approves major expansion of postgraduate and undergraduate medical education capacity in the country,” Press Information Bureau, Cabinet, September 24, 2025, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2170588®=3&lang=2>
- ¹⁴⁵ Starred Question No 193, Lok Sabha, Ministry of Health and Family Welfare, December 12, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AS193_Lf3gdq.pdf?source=pqals.
- ¹⁴⁶ https://sansad.in/getFile/annex/268/AU1876_rsdkaL.pdf?source=pqars.
- ¹⁴⁷ Starred Question No 89, Lok Sabha, Ministry of Health and Family Welfare, December 5, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AS89_R1Xn1F.pdf?source=pqals.
- ¹⁴⁸ PM Vidya Laxmi Scheme, Ministry of Education, Lok Sabha, August 4, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU2421_AajJTd.pdf?source=pqals.
- ¹⁴⁹ PM Vidya Laxmi Dashboard, Ministry of Education, as accessed on December 24, 2025, <https://pmvidyalaxmi.co.in/PublicDashboard.aspx>.
- ¹⁵⁰ Three Hundred and Seventy Second Report of the Standing Committee on Education, Rajya Sabha, December 9, 2025, https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/16/214/372_2025_12_12.pdf?source=rajyasabha.
- ¹⁵¹ Unstarred Question No 996, “New Universities for Expansion of Higher Education in the Country” Ministry of Education, Rajya Sabha, December 12, 2024 https://sansad.in/getFile/annex/266/AU996_2Z8C7.pdf?source=pqars.
- ¹⁵² India’s Higher Education from Tradition to Transformation, Press Information Bureau, February 13, 2025, <https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=149132®=3&lang=2>.
- ¹⁵³ Three Hundred and Sixty Fourth Report of the Standing Committee on Education, Rajya Sabha, March 26, 2025, https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/16/198/364_2025_3_15.pdf?source=rajyasabha.
- ¹⁵⁴ Research and Development Statistic at a glance 2022-23, Ministry of Science and Technology, <https://dst.gov.in/sites/default/files/R%26D%20Statistics%20at%20a%20Glance%202022-23.pdf>.
- ¹⁵⁵ India rises in QS World Rankings 2026, Press Information Bureau, June 19, 2025, <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?id=154694&NoteId=154694&ModuleId=3®=3&lang=2>.
- ¹⁵⁶ QS World Asia Rankings 2026, <https://www.topuniversities.com/asia-university-rankings?search=india>.
- ¹⁵⁷ “Houses for all under Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin,” December 13, 2022, Press Information Bureau, Ministry of Rural Development, <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1883183>.
- ¹⁵⁸ “Cabinet approves continuation of Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban (PMAY-U) - “Housing for All” Mission up to 31st December 2024”, August 10, 2022, Press Information Bureau, <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1850679>.
- ¹⁵⁹ Cabinet approves implementation of the Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin (PMAY-G) during FY 2024-25 to 2028-29, Ministry of Rural Development, PIB, August 9, 2024, <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2043921>.
- ¹⁶⁰ PMAY (G) Dashboard, Ministry of Rural Development, as accessed on December 27, 2025, <https://pib.gov.in/netiav/PBIDashboard/PMAYGDashboard.aspx>.

- ¹⁶¹ Achievement under PMAY-U & PMAY-U 2.0, Ministry of Urban Affairs, as accessed on January 12, 2026, https://pmay-urban.gov.in/uploads/progress-pdfs/68ac528160e77-Achievement_under_PMay-U_&_PMAY-U2.0_cropped.pdf.
- ¹⁶² Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban 2.0, Press Information Bureau, Ministry of Urban Affairs, August 10, 2024, <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=152011&ModuleId=3®=3&lang=1>.
- ¹⁶³ Introduction, Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihood Mission, Ministry of Rural Development, accessed on June 15, 2024, <https://aajeevika.gov.in/about/introduction>.
- ¹⁶⁴ Bank Credit to Women SHGs, Unstarred Question No 3025, Ministry of Rural Development, Rajya Sabha, December 20, 2024, https://sansad.in/getFile/annex/266/AU3025_UtFvZ3.pdf?source=pqars.
- ¹⁶⁵ Starred Question No 138, Lok Sabha, Ministry of Rural Development, July 29, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AS138_slGOkB.pdf?source=pqals.
- ¹⁶⁶ Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Programme Guidelines, Ministry of Rural Development, January, 2015, https://pmsgy.nic.in/sites/default/files/pdf/PMGSY_E_J_2015.pdf.
- ¹⁶⁷ Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Dashboard, Ministry of Rural Development, as accessed on December 28, 2025, <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrjoiZTY1YzdkYWUtMjY1Y00ZGM2LWJlZTItMTVmNTJmODkxMGJhIiwidCI6IjliZjc5NjA5LWU0ZTg1NDdhZC1hYTUzLTl0NjQ2MTg1NTM4YyJ9>.
- ¹⁶⁸ Cabinet approves implementation of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana - IV (PMGSY-IV) during FY 2024-25 to 2028-29, Press Information Bureau, September 11, 2024, <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2053894>.
- ¹⁶⁹ Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, NQM, Regarded Grading Abstract, as accessed on January 20, 2025, <https://omms.nic.in/#>
- ¹⁷⁰ Untarred Question No 2004, Lok Sabha, Ministry of Panchayati Raj, December 17, 2025, https://sansad.in/getFile/annex/269/AU2004_JbBYk.pdf?source=pqars.
- ¹⁷¹ Scheme Dashboard, SVAMITVA, Ministry of Rural Development, as accessed on January 5, 2025, https://svamitva.nic.in/svamitva_hindi/index.html#home.
- ¹⁷² Unstarred Question No 2682, Lok Sabha, Ministry of Home Affairs, December 16, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU2682_eR70oE.pdf?source=pqals.
- ¹⁷³ “Defence Aatmanirbharta: Record Production and Exports” Press Information Headquarters, November 20, 2025, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2191937®=3&lang=2>.
- ¹⁷⁴ “Make in India Powers Defence Growth” Press Information Bureau, Ministry of Defence, March 29, 2025, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2116612®=3&lang=2>.
- ¹⁷⁵ “Defence Aatmanirbharta: Record Production and Exports” Press Information Headquarters, November 20, 2025, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2191937®=3&lang=2>.
- ¹⁷⁶ SIPRI Yearbook 2025, Stockholm International Peace Research Institute, https://www.sipri.org/sites/default/files/2025-06/yb25_summary_en.pdf.
- ¹⁷⁷ 3rd Report: Demands for Grants (2024-25), Capital Outlay on Defence Services, Procurement Policy and Defence Planning, Standing Committee on Defence, Lok Sabha, December 17, 2024, https://sansad.in/getFile/Isscommittee/Defence/18_Defence_3.pdf?source=loksabhadocs.
- ¹⁷⁸ Department of Defence Production webpage, as accessed on December 29, 2025, <https://www.ddpmod.gov.in/offering/schemes-and-services/index>.
- ¹⁷⁹ “Aatmanirbhar Bharat: iDEX-DIO & EdCIL (India) Ltd ink MoU to develop dual-use tech under new ASPIRE program” Press Information Bureau, Ministry of Defence, September 2025, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2164966®=3&lang=2>.
- ¹⁸⁰ “Department of Science and Technology- Year Ender 2025” Press Information Bureau, Ministry of Science and Technology, December 16, 2025, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2204761®=3&lang=1>.
- ¹⁸¹ Scientific publications, Press Information Bureau, Ministry of Science and Technology, March 12, 2025, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2110770®=3&lang=2>.
- ¹⁸² Unstarred Question No 2767, Lok Sabha, Ministry of Science and Technology, December 17, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU2767_mtKqR2.pdf?source=pqals.
- ¹⁸³ Unstarred Question No 499, Lok Sabha, Ministry of Science and Technology, December 3, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU499_H7srwL.pdf?source=pqals.
- ¹⁸⁴ Unstarred Question No 459, Lok Sabha, Ministry of Science and Technology, April 2, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AS459_icqNXs.pdf?source=pqals.
- ¹⁸⁵ “Transforming India with AI” Press Information Bureau Headquarters, October 12, 2025, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2178092®=3&lang=2#_ftn5.
- ¹⁸⁶ Global Cybersecurity Index, 2024, International Telecommunication Union, <https://www.itu.int/epublications/publication/global-cybersecurity-index-2024>.
- ¹⁸⁷ Unstarred Question No 2297, Rajya Sabha, Ministry of Electronics and Information Technology, December 19, 2025, https://sansad.in/getFile/annex/269/AU2297_kOmEUX.pdf?source=pqars.
- ¹⁸⁸ Unstarred Question No 2067, Rajya Sabha, Ministry of Tribal Affairs, August 6, 2025, https://sansad.in/getFile/annex/268/AU2067_DGiG35.pdf?source=pqars.
- ¹⁸⁹ Eklavya Model Residential Schools, Ministry of Tribal Affairs, as accessed on January 7, 2025, <https://tribal.nic.in/EMRS.aspx>.

डिस्क्लेमर: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूप या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।